वर्ष 12 • अंक 266 • 10 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 26 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

पुराने चावल से जैव ईंधन बनाने की तैयारी

पिरोजशा गोदरेज ▸▸ पृष्ठ 3

अच्छी जमीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का दांव

एक नज़र

क्रिसमस पर बंद रहे शेयर और जिंस बाजार

क्रिसमस पर बुधवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिंस वायदा बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अवकाश रहा। सराफा और सभी प्रमुख थोक बाजार भी बंद रहे।

निर्गम से अधिक आवेदन भी शामिल करेगी सरकार

सरकार ने ग्रीन शू विकल्प के तहत तीन साल और दस साल की शृंखला वाले भारत बॉन्ड ईटीएफ में मिले अधिक अभिदान को बनाए रखने का फैसला किया है। तीन साल वाली श्रेणी में 6,982 करोड़ रुपये मूल्य के यूनिट्स के लिए आवेदन आए जो कुल यूनिट्स से करीब 2.2 गुना अधिक थे। इसी तरह दस वर्षीय श्रेणी में 5,413 करोड़ रुपये के आवेदन प्राप्त हुए जबकि निर्गम का आकार 4,000 करोड़ रुपये का था।

भारत में इंजन इकाई लगाने पर विचार कर रही सैफ्रन

फ्रांस स्थित सैफ्रन ग्रुप भारत में विमान इंजनों के लिए मैंटेनेंस रिपेयर ऐंड ओवरहॉल इकाई स्थापित करने की योजना बना रही है। इस इकाई पर कंपनी 15 करोड़ डॉलर निवेश कर सकती है। अमेरिका की सीएफएम इंटरनैशनल में सैफ्रन और जीई एविएशन की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। सीएफएम द्वारा निर्मित इंजनों का इस्तेमाल एयरबस ए320 और बोइंग 737 जैसे विमानों में किया जाता है। पृष्ठ 2

तेल-गैस विवाद दूर करने के लिए समिति का गठन

सरकार ने तेल एवं गैस के अन्वेषण और उत्पादन से जुड़े विवादों के एक निश्चित समय सीमा में समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के गठन से लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया सहारा नहीं लेना होगा। तेल एवं गैस मुद्दों से जुड़े विवादों से इस क्षेत्र में निवेश पर नकारात्मक असर हो रहा है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार पूर्व तेल एवं गैस सचिव जी सी चतुर्वेदी, ऑयल इंडिया लिमिटेड के पूर्व प्रमुख विकास सी बोरा और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सतीश पुरी इस समिति के सदस्य होंगे।

औषधि मूल्य नीति पर हो रहा विचार

दवा विनिर्माताओं की ओर से दवाओं के दाम तय करने संबंधी किसी भी बदलाव को दवा के अगले बैच से लागू करने की लंबे समय से लंबित मांग की सरकार समीक्षा कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगर प्राधिकरण को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 (डीपीसीओ 2013) में संशोधन की जरूरत महसूस होती है तो उस पर फैसला करेगा। पृष्ठ 4

पाकिस्तान भारत से मंगाएगा पोलियो मार्कर

पाकिस्तान ने भारत ने पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय लिया है। अगस्त में जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार निलंबित कर दिया था। बुधवार को पाकिस्तान के मीडिया में आई खबरों के अनुसार वहां की सरकार ने भारत से पोलियो मार्कर मंगाने की मंजूरी दे दी है। खबरों के अनुसार यह मंजूरी एक बार के लिए दी गई है।

बीते दशक में निवेश पर वास्तविक रिटर्न करीब 2 फीसदी रहा

जयदीप घोष
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

बंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक भले ही सर्वकालिक उच्च स्तर 41,000 के पार पहुंच गया हो लेकिन पिछले एक दशक में शेयरों का नॉमिनल रिटर्न 9 फीसदी की सालाना चक्रवृद्धि दर (सीएजीआर) के हिसाब से मिला है। मिड और स्मॉल कैप सूचकांकों का रिटर्न इस दौरान सेंसेक्स से भी कम रहा है।

बिड़ला सन लाइफ म्युचुअल फंड के मुख्य कार्याधिकारी ए बालासुब्रमणयन ने कहा, 'शेयर का रिटर्न व्यापक तौर पर नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और कंपनियों की आय में वृद्धि से जुड़ा होता है। 1990 के दशक की शुरुआत और पिछले दशक में इसमें खासी तेजी देखी जा रही थी। लेकिन धीरे-धीरे इसमें नरमी आने लगी। इसके परिणामस्वरूप शेयर में निवेश पर रिटर्न भी कम हो गया।'

उनके अनुसार मुद्रास्फीति के निचले स्तर पर बने रहने से ब्याज दरें भी कम होनी चाहिए। हालांकि इसमें देरी हुई और पूरी तरह से इसे संतुलित नहीं किया गया, जिसका असर कंपनियों की संभावित आय वृद्धि पर पड़ा और रिटर्न भी कम मिला।

अन्य बचत और निवेश साधनों में रिटर्न कम रहा है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक का एक साल की सावधि जमा पर अभी 6.25 फीसदी ब्याज मिल रहा है। हालांकि 2011 में रिटर्न 9.3 फीसदी के उच्च स्तर तक और 2013 में 9 फीसदी तक पहुंच गया था लेकिन 2015 के बाद से इसमें लगातार कमी आ रही है।

एक दशक में बदला परिदृश्य

मिरे ऐसेट मैनेजमेंट में फिक्स्ड इनकम प्रमुख महेंद्र जाजू ने कहा, 'भारत वैश्विक बाजारों से काफी हद तक जुड़ा हुआ है, खास तौर पर विदेशी निवेशकों द्वारा शेयर और बॉन्ड बाजार में निवेश के मामले में। ऐसे में ब्याज दरें वैश्विक बाजारों के अनुरूप होती हैं।' उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ब्याज दरों में और कमी आ सकती है।

दूसरी ओर सोने पर रिटर्न सेंसेक्स की तरह ही 8.7 फीसदी सीएजीआर रहा। हालांकि रुपये में नरमी की वजह से सोने पर रिटर्न बढ़ा है। दिसंबर 2009 में डॉलर के मुकाबले रुपया 46.5 पर था जो अब प्रति डॉलर 71.2 रुपये पर आ गया है। पिछले दकश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने में रिटर्न महज 3.1 फीसदी सीएजीआर रहा।

रिटर्न में अगर मुद्रास्फीति को समायोजित कर दें तो वास्तविक रिटर्न और भी कम रहा है। दशक की पहली छमाही में मुद्रास्फीति सालाना दो अंक में बढ़ी थी, जिससे निवेशकों का वास्तविक रिटर्न घटा था।

सावधि जमा कभी मुद्रास्फीति को मात नहीं दे पाई और शेयर तथा सोने पर वास्तविक रिटर्न उस दौरान 2 से 3 फीसदी रहा। दूसरी ओर उससे पिछले दशक (2000-2009) में शेयर और सोने पर नॉमिनल रिटर्न दो अंक में रहा जबकि मुद्रास्फीति 5.5 फीसदी रही थी।

कोटक म्युचुअल फंड के प्रबंध निदेशक निलेश शाह ने पिछले दशक में कम रिटर्न के पीछे दूसरा कारण बताया। उन्होंने कहा, 'रिटर्न कम रहने की मुख्य वजह अर्थव्यवस्था में नरमी रही, जिसकी वजह से कई लॉर्ज कैप्स की रेटिंग घटानी पड़ी। हालांकि इसके बावजूद भारत प्रतिस्पर्द्धी बाजारों में दूसरा सबसे अच्छा इक्विटी बाजार रहा है।'

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पीपीएफ, किसान विकास पत्र जैसी लघु बचत योजनाओं पर ब्याज घटता है तो बैंकों के ब्याज दरों में आगे और कमी आ सकती है। एक डेट फंड मैनेजर ने कहा, 'बैंकों की सावधि जमा दरों में ज्यादा कमी इसलिए नहीं आई है क्योंकि बैंकरों को डर है कि दरें घटाने से निवेशक सावधि जमा से पैसा निकलकर लघु बचत योजनाओं में लगा सकते हैं।'

एक दशक में किसने दिया कितना रिटर्न...

	31 दिसं., 2009 बंद	10 साल सीएजीआर (%)	वास्तविक रिटर्न (औसत मुद्रास्फीति 5.55%)	24 दिसं., 2019 बंद	10 साल सीएजीआर (%)	वास्तविक रिटर्न (औसत मुद्रास्फीति 6.20%)**
बीएसई सेंसेक्स	17,464.8	13.31	7.76	41,461.3	9.00	2.80
एनएसई निफ्टी 50	5,201.1	13.39	7.84	12,214.5	8.87	2.67
बीएसई स्मॉलकैप्स*	8,357.6	9.20	3.65	13,384.3	6.00	-0.20
बीएसई मिडकैप्स*	6,717.8	5.60	0.05	14,820.2	8.20	2.00
सोना	16,690.0	13.93	8.38	38,291.0	8.70	2.50
~ बनाम $	46.50	—	—	71.27	—	—
एसबीआई एफडी	6.00	—	0.45	6.25	—	0.05

*बीएसई स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स आंकड़े 11 अप्रैल, 2005 से, **नवंबर 2019 तक2019
स्रोत : ब्लूमबर्ग/बीजेए। संकलन : बीएस रिसर्च
नई शृंखला जनवरी 2012 से

टाटा संस में नहीं लौटेंगे साइरस!

टाटा संस में चेयरमैन पद संभालने की जगह बोर्ड में कर सकते हैं नॉमिनी नियुक्त

श्रीमी चौधरी
मुंबई, 25 दिसंबर

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने साइरस मिस्त्री को पिछले सप्ताह टाटा संस और समूह की तीन अन्य कंपनियों के चेयरमैन के रूप में बहाल कर दिया था लेकिन इन कंपनियों के बोर्ड में कोई पद लेने की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वह एक नॉमिनी निदेशक नियुक्त कर सकते हैं जो टाटा समूह की कंपनियों में कामकाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगा।

सूत्रों का कहना है कि मिस्त्री टाटा समूह की कंपनियों के कामकाज का हिस्सा बने बगैर उन पर कारगर निगरानी रखना चाहते हैं। चेयरमैन के रूप में अब उनका केवल पांच महीने का समय बाकी रह गया है और यही वजह है कि वह बोर्ड में वापसी के इच्छुक नहीं हैं। वह 2006 में निदेशक के तौर पर टाटा संस से जुड़े थे। मिस्त्री के करीबी सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में वह चेयरमैन के पद के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे।

माना जा रहा है कि टाटा संस एनसीएलएटी के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकता है। इसके मद्देनजर मिस्त्री और उनकी टीम कानूनी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उच्चतम न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है।

हालांकि सूत्रों की मानें तो अगर उच्चतम न्यायालय पंचाट के आदेश को बरकरार रखता है तब भी मिस्त्री के बोर्ड में कार्यकारी चेयरमैन या निदेशक बनने की संभावना नहीं है। एनसीएलएटी ने टाटा संस को आदेश दिया है कि मिस्त्री को होल्डिंग कंपनी और तीन सूचीबद्ध कंपनियों के चेयरमैन और निदेशक के रूप में बहाल किया जाए। इनमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टाटा मोटर्स और टाटा स्टील शामिल हैं। टाटा को अपील करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है और इस दौरान पंचाट के आदेश का क्रियान्वयन नहीं होगा।

मिस्त्री ने राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) और एनसीएलएटी में अपनी याचिका में टाटा समूह की कंपनियों में कॉरपोरेट प्रशासन की बदहाली और निदेशक मंडलों की नाकामी का आरोप लगाया था। अपने नॉमिनी के माध्यम से मिस्त्री टाटा की कंपनियों में कॉरपोरेट प्रशासन में सुधार सुनिश्चित करेंगे और भविष्य में उनका कारोबार बढ़ाने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दिलचस्प बात है कि अक्टूबर 2016 में जब मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाया गया था तो उन्हें समूह की कंपनियों में निदेशक पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब टाटा संस के उन्हें चेयरमैन और निदेशक के पद से हटाने के लिए इन कंपनियों की असाधारण आम बैठक बुलाई तो उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया।

सूत्रों ने कहा कि मिस्त्री का मानना है कि पिछले तीन साल टाटा समूह की कंपनियों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे हैं और इसकी वजह यह है कि उनमें कामकाज के बेहतर ढांचे का अभाव है। मिस्त्री ने 2016 में टाटा संस के बोर्ड को भेजे पत्र में विमानन उद्योग में निवेश की आलोचना की थी और वह संयुक्त उपक्रम विस्तारा और एयरएशिया इंडिया के खिलाफ थे। एक सूत्र ने कहा, 'उड्डयन क्षेत्र में भारी निवेश के अलावा टाटा संस ने पिछले तीन साल में किसी भी रणनीति में बदलाव नहीं किया है। उड्डयन क्षेत्र में भी उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि समूह में आंतरिक नियंत्रण लचर है।' उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में मिस्त्री के अनुमान से ज्यादा नुकसान हुआ है।

2016 में टाटा संस के बोर्ड सदस्यों को भेजे गए एक गोपनीय ईमेल में मिस्त्री ने चेतावनी दी थी कि उन्हें विरासत में पांच घाटे वाले कारोबार मिले हैं जिनके कारण टाटा समूह को 1.18 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डालने पड़ सकते हैं।

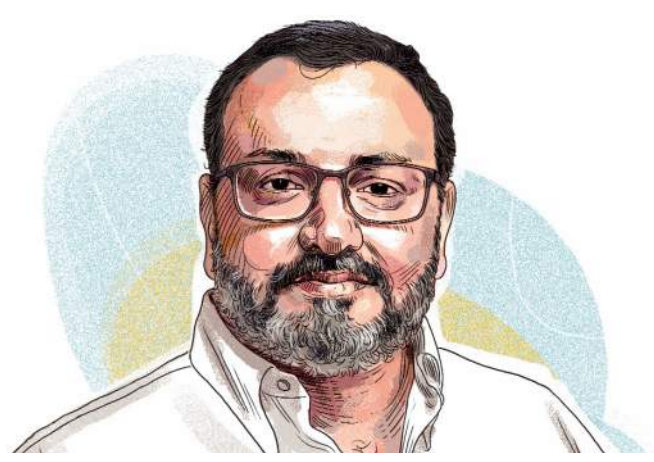

- एनसीएलएटी ने साइरस को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल करने का दिया था आदेश
- साइरस टाटा की कंपनियों पर चाहते हैं कारगर निगरानी
- चेयरमैन के रूप में केवल 5 महीने का समय बाकी
- उच्चतम न्यायालय में लड़ने की तैयारी

जीएसटी शिकायतों के लिए बनेगी व्यवस्था

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

- हर राज्य और कर क्षेत्र में बनेगी समिति
- कर अधिकारी, सलाहकार और व्यापारिक प्रतिनिधि होंगे शामिल
- नीतिगत बदलावों के लिए दे सकती है सुझाव
- शिकायत दर्ज करने के लिए बनेगा पोर्टल

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित विभिन्न पक्ष अब इससे जुड़े कानूनों और नियमों में नीतिगत बदलाव के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने देश के सभी कर क्षेत्रों और राज्यों में शिकायत निपटान समिति के गठन के लिए जीएसटी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इन समितियों में कर अधिकारी, सलाहकार और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समितियां विभिन्न पक्षों से जीएसटी के बारे में उनकी शिकायत पर प्रतिक्रिया लेकर जीएसटी परिषद और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) को सुझाव देंगी। मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक इनमें नीतिगत स्तर के बदलाव के सुझाव भी शामिल होंगे।

जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह इस तरह की समिति के गठन को मंजूरी दी थी। केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्त और क्षेत्र या राज्य के मुख्य आयुक्त समिति के सह-अध्यक्ष होंगे। हर समिति में व्यापारिक संगठनों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होगी। मंत्रालय के मुताबिक इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकार और कर विशेषज्ञ के रूप में चार सदस्य होंगे। यह समिति करदाताओं के समक्ष पेश आ रही विभिन्न समस्याओं की समीक्षा और समाधान करेगी। इनमें प्रक्रियागत समस्याएं और आईटी से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

यह जीएसटी कानूनों, नियमों, अधिसूचनाओं, फॉर्म और परिपत्र में बदलावों से जुड़े मामलों को जीएसटी परिषद सचिवालय और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के पास भेज सकती है। मंत्रालय ने कहा कि समिति जीएसटी पोर्टल से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित मामलों को जीएसटीएन को भेज सकती है।

अगर समिति जीएसटी नीति से संबंधित किसी मामले को भेजती है तो सीबीआईसी की संबंधित नीति शाखा इसकी समीक्षा करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इसे जीएसटी परिषद के समक्ष रखा जाएगा। जीएसटीएन शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक पोर्टल विकसित करेगा ताकि इन शिकायतों का समय पर निपटारा किया जा सके। यह सुनिश्चित करना समिति के सह-अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि शिकायतें समय पर दर्ज की जाएं और पोर्टल पर उनके निपटान से संबंधित जानकारी को अपडेट किया जाए। शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी पोर्टल पर दिखाई जाएगी ताकि हर कोई इसे देख सके।

अगर किसी क्षेत्र में एक से ज्यादा राज्य हैं तो हर राज्य में समिति का गठन किया जाएगा। इसी तरह अगर किसी राज्य में एक से अधिक क्षेत्र हैं तो हर क्षेत्र में समिति का गठन किया जाएगा। इन समितियों का गठन दो वर्ष के लिए किया जाएगा। अगर कोई सदस्य बिना किसी कारण के लगातार तीन बैठकों में शामिल नहीं होता है तो माना जाएगा कि उसने समिति से इस्तीफा दे दिया है।

जल जीवन मिशन का दिशानिर्देश जारी

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

- केंद्र स्तर पर जल जीवन मिशन
- राज्य स्तर पर जल एवं स्वच्छता मिशन
- जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
- ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत एवं उसकी उप-समितियां

सरकार पेय जल आपूर्ति सेवा में संरचनात्मक बदलाव लाना चाहती है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी 'जल जीवन मिशन' के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार पेय जल सेवा को उपयोगिता आधारित नजरिये के साथ आगे बढ़ाना चाहती है। दिशानिर्देशों के अनुसार इससे संस्थान सेवाओं पर अधिक ध्यान दे पाएंगे और जल शुल्क या उपभोक्ता शुल्क के संग्रह में आसानी होगी। 14.6 करोड़ घरों तक नल के माध्यम से जल पहुंचाने की इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर 3.60 लाख करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार 2.08 लाख करोड़ रुपये अंशदान देगी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में 81.67 प्रतिशत परिवारों में नल के जरिये जल की आपूर्ति संभव नहीं हो पाई है। राज्यों में परिचालन एवं रखरखाव, खासकर पाइप से जल आपूर्ति पर आने वाले खर्च से निपटने के लिए, नीति तैयार की जाएगी। दिशानिर्देशों के अनुसार इससे राज्य उपभोक्ता समूहों से शुल्क वसूल सकेंगे, जिससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ नहीं बढ़ेगा। इस मिशन के लिए केंद्र अतिरिक्त संसाधन भी मुहैया कराएगा। इस राशि का आवंटन राज्यों के बीच सकल बजट प्रावधान के साथ किया जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार इस मिशन में जिन राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उन्हें सरकार दूसरे राज्यों में इस्तेमाल नहीं हुआ धन देकर प्रोत्साहन देगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर ही केंद्र द्वारा जारी धन एक 'एकल अधिकृत खाते' में रहेगा और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन इस खाते का रखरखाव करेगा। इस रकम पर लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली नजर रखेगी। एसडब्ल्यूएसएम इस परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए अनुबंध की शर्त तैयार करने के साथ केंद्रीकृत निविदा के जरिये जानी-मानी निर्माण एजेंसियों/वेंडरों की नियुक्ति करेगी। योजना पर आने वाले परिचालन एवं रखरखाव से जुड़े खर्च जैसे बिजली बिल, नियमित कर्मचारियों का वेतन और जमीन की खरीद आदि के लिए केंद्र के हिस्से से राशि खर्च करने की अनुमति नहीं होगी। दिशानिर्देश में कहा गया है, 'मंजूर योजना से इतर समानांतर जल आपूर्ति ढांचा तैयार करने से रोकने के लिए जल आपूर्ति योजना हेतु विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध रकम की समीक्षा एवं इसका संग्रहण करने का प्रस्ताव है। एमपीएलएडीएस, एमएलएलएडीएस, डीएमडीएफ या राज्य या ग्रामीण स्तर पर दान के रूप में आई रकम का इस्तेमाल कड़ाई से होगा।' जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतें नियोजन, ढांचा निर्माण, क्रियान्वयन, परिचालन और रखरखाव में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। राज्य सरकार इस योजना में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की पहचान कर उन्हें इस योजना से जोड़ेगी। हरेक गांव को ग्रामीण कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिनमें तीन पहलू- जल स्रोत एवं इनका रखरखाव, जलापूर्ति और ग्रे वाटर मैनेजमेंट- शामिल होंगे। गांवों द्वारा तैयार कार्य योजनाएं जिला स्तर पर पेश होंगी और उसके बाद राज्य कार्य योजना तैयार करने में इनका इस्तेमाल होगा। दिशानिर्देश में कहा गया है, 'राज्य कार्य योजना से एक विस्तृत नजरिया सामने आएगा, खासकर क्षेत्रीय ग्रिड, एकमुश्त जल आपूर्ति और वितरण परियोजनाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी।

व्यापार गोष्ठी

कारोबार के लिहाज से कैसा रहा साल 2019?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या जीएसटी शिकायत के लिए अलग व्यवस्था से दूर होगी दिक्कत

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या एनआरसी पर अमित शाह के बयान से थम जाएगा घमासान?	हां	65.00%
	नहीं	35.00%

संक्षेप में

सनमार केमिकल्स ग्रुप संग फेयरफैक्स सौदा पूरा

फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉरपोरेशन (फेयरफैक्स इंडिया) ने चेन्नई की सनमार केमिकल्स ग्रुप संग घोषित पहले का सौदा पूरा कर लिया है। हालिया इक्विटी निवेश के बाद फेयरफैक्स इंडिया की इक्विटी सनमार में बढ़कर करीब 43 फीसदी हो गया। सौदे के तहत सनमार ने फेयरफैक्स इंडिया के पास मौजूद करीब 30 करोड़ डॉलर के बॉन्ड (और उस पर अर्जित 13 फीसदी सालाना ब्याज) करीब 42.5 करोड़ डॉलर की नकदी के जरिये खरीद लिए। फेयरफैक्स इंडिया ने बॉन्ड की बिक्री से मिली रकम में से 20 करोड़ डॉलर का निवेश सनमार के शेयर खरीदने में कर दिया। इस इक्विटी निवेश के बाद फेयरफैक्स इंडिया की इक्विटी सनमार में बढ़कर करीब 43 फीसदी हो गया। *बीएस*

2020 के अंत तक 11 नए होटल खोलेगी हयात

वैश्विक होटल कंपनी हयात होटल्स कॉरपोरेशन की 2020 के अंत तक भारत में 11 नए होटल खोलने की योजना है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत में विस्तार की योजना के तहत हम 11 नए होटल खोलने जा रहे हैं। शिकागो मुख्यालय वाली कंपनी के फिलहाल भारत में 20 स्थानों पर 32 होटल हैं। हयात के पोर्टफोलियो के भारत में आठ ब्रांड हैं....हयात, हयात सेंट्रिक, हयात रीजेंसी, हयात प्लेस, ग्रैंड हयात, पार्क हयात, अलीला और अंदाज। हयात के भारतीय परिचालन के उपाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा, 'हमारी 2020 के अंत तक भारत में 11 नए होटल खोलने की योजना है। भारत हमारी वृद्धि की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण बाजार है।' हयात भारत में उतरने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय होटल प्रबंधन ब्रांड में से एक है। *भाषा*

जर्मनी की रिटेल कंपनी की राजस्व वृद्धि में आया सुधार, मुनाफे की दौड़ में

प्रतिस्पर्धियों से आगे निकली मेट्रो

अर्णव दत्ता
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

जर्मन होलसेल रिटेल दिग्गज मेट्रो कैश ऐंड कैरी इंडिया स्थानीय बाजार में अपनी दो अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों को मात देने में सफल रही है। देश में लगभग 15 साल पहले अपना पहला स्टोर खोलने वाली मेट्रो 2018-19 में पहली बार मुनाफे की स्थिति में आकर वॉलमार्ट और एमेजॉन होलसेल जैसी प्रतिस्पर्धियों को मात देने में सफल रही है।

कंपनी पंजीयक के साथ मौजूद जानकारी के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष के दौरान मेट्रो ने 217.4 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि दो अमेरिकी कंपनियां इस अवधि में नुकसान में रहीं। जहां एमेजॉन होलसेल ने 141 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान दर्ज किया, वहीं 2018-19 में वॉलमार्ट का शुद्ध नुकसान 172 करोड़ रुपये पर रहा।

मेट्रो की राजस्व वृद्धि इन दोनों प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले मजबूत बनी हुई है। कंपनी ने 2018-19 में 6,533 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व दर्ज किया, जो 2017-18 में उसके द्वारा दर्ज किए गए 5,807 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 13 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं वॉलमार्ट इंडिया का राजस्व 2018-19 में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 4,065 करोड़ रुपये पर रहा। एमेजॉन होलसेल का राजस्व सालाना आधार पर 8 प्रतिशत घटकर 11,232 करोड़ रुपये रहा।

मेट्रो कैश ऐंड कैरी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी अरविंद मेडिरेट्टा ने कहा कि मेट्रो ने लगातार दो वर्षों (अक्टूबर, 2018 से सितंबर 2019 और अक्टूबर 2017 से सितंबर 2018) के लिए मुनाफा दर्ज किया। हालांकि उन्होंने इन आंकड़ों के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, '30 सितंबर, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में हमारा राजस्व 6,130 करोड़ रुपये की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़कर 6,700 करोड़ रुपये रहा।'

वहीं वॉलमार्ट और एमेजॉन जैसे अन्य रिटेल कंपनियों को भारी छूट की वजह से लगातार नुकसान का सामना करना पड़ा है। मेडिरेट्टा ने राजस्व में सुधार के लिए अपने साथ काम करने वाले 800,000 किराना स्टोरों के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत मुहैया कराने की मेट्रो की दक्षता को जिम्मेदार बताया। मेट्रो ने ज्यादा मार्जिन वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने पोर्टफोलियो में बदलाव किया है।

अपना मार्जिन सुधारने के लिए मेट्रो ने योगर्ट, फ्रोजन फूड, स्नैक्स और जूस, चॉकलेट और मसाले जैसे उत्पादों पर ध्यान दिया है जिससे उसे ज्यादा मार्जिन हासिल करने में मदद मिली है। कंपनी अपने सैकड़ों घरेलू उत्पादों का मार्जिन सुधारने में सफल रही है।

मेडिरेट्टा ने कहा कि दिल्ली और बेंगलूरु में लगभग एक साल तक अपना स्मार्ट-किराना कार्यक्रम चलाने के बाद अब भारतीय इकाई को पूरे भारत में इस कार्यक्रम के विस्तार की अनुमति मिल गई है। इस कार्यक्रम के तहत, होलसेल दिग्गज पीओएस डिवाइस के जरिये भागीदार किराना आउटलेटों को अत्याधुनिक बनाती है और दुकान मालिकों के साथ साथ ग्राहकों के लिए आसान ऋण योजनाओं की पेशकश करती है।

मजबूत हो रही मुनाफे की रफ्तार

- जर्मन रिटेल कंपनी अपनी अमेरिकी प्रतिस्पर्धियों के विपरीत 2018-19 में मुनाफे की स्थिति में आने में सफल रही
- मेट्रो ने अक्टूबर-सितंबर, 2019 में 6,700 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया
- अक्टूबर-सितंबर वित्त वर्ष पर अमल करने वाली कंपनी लगातार दो वर्षों से मुनाफे की स्थिति में बनी हुई है
- कंपनी ने वर्ष 2020 में महानगरों और छोटे शहरों में 5-6 नए स्टोर खोलने की योजना बनाई है

भारत में इंजन इकाई लगाने पर विचार कर रही सैफ्रन

अनीश फडणीस
मुंबई, 25 दिसंबर

फ्रांस का सैफ्रन ग्रुप अपने एयरलाइन ग्राहकों की तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में विमान इंजनों के लिए मैंटेनेंस रिपेयर ऐंड ओवरहॉल (एमआरओ) इकाई पर 15 करोड़ डॉलर के निवेश पर विचार कर रहा है।

अमेरिका स्थित सीएफएम इंटरनैशनल में सैफ्रन और जीई एविएशन की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। सीएफएम द्वारा निर्मित इंजनों का इस्तेमाल एयरबस ए320 और बोइंग 737 जैसे विमानों में किया जाता है।

अगले पांच साल के दौरान भारत में लगभग 1,000 सीएफएम इंजन बनाए जाएंगे

मौजूदा समय में, भारत में लगभग 220 एयरबस और बोइंग विमानों में ये इंजन लगे हुए हैं। इसके अलावा कंपनी को इंडिगो, स्पाइसजेट और विस्तारा के 485 विमानों में सीएफएम इंजन लगाने का ऑर्डर मिला है। ये इंजन अगले पांच साल में सौंपे जाएंगे। इसका मतलब होगा कि आने वाले वर्षों में भारत में लगभग 1,000 नए इंजन परिचालन में होंगे।

सीएफएम इंटरनैशनल इंजन निर्माता प्रैट ऐंड व्हिटनी के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और उसने इंडिगो से जून में 280 एयरबस ए320 नियो के लिए इंजन आपूर्ति का 20 अरब डॉलर का अनुबंध हासिल किया। इस बड़े अनुबंध को मिलने के बाद कंपनी ने भारत में एमआरओ स्थापित करने की योजना पर ध्यान केंद्रित किया है।

भारत में एमआरओ संयंत्र की स्थापना की योजना के बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सैफ्रन ने कहा, 'भारतीय एयरोस्पेस उद्योग के दीर्घावधि भागीदार के तौर पर सैफ्रन यहां वृद्धि में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। एशिया और खासकर भारत में सीएफएम इंजनों के तेज विस्तार को देखते हुए हम एमआरओ की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत में नई इकाई तैयार करने की संभावना तलाश रहे हैं। यह नया संयंत्र 15 करोड़ डॉलर से ज्यादा के निवेश से जुड़ा होगा।'

मौजूदा समय में, सिर्फ एयर इंडिया के पास विमान इंजनों के घरेलू तौर पर मैंटेनेंस के लिए सुविधाएं मौजूद हैं जबकि अन्य सभी एयरलाइन मरम्मत के लिए अपने इंजन देश से बाहर भेजती हैं। घरेलू एमआरओ से भारतीय एयरलाइनों को विदेशी मुद्रा से संबंधित खर्च घटाने में मदद मिलेगी और साथ ही इससे इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सैफ्रन के अधिकारियों की एक टीम ने कुछ महीने पहले मुंबई में एयर इंडिया की एमआरओ इकाइयों का दौरा किया था और इस एयरलाइन की क्षमताओं का आकलन किया था। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि भारत में श्रम लागत यूरोप या अमेरिका के मुकाबले आधी है और इससे अन्य एयरलाइनों के लिए मैंटेनेंस इकाई बेहद उपयोगी साबित होगी।

सैफ्रन ग्रुप अपनी एमआरओ के लिए कर एवं नियामकीय ढांचे से संबंधित मामलों पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है। भारत में, विमानों की मरम्मत से जुड़े कार्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है और हवाई अड्डा ऑपरेटर भी एमआरओ व्यवसाय पर ऊंचे शुल्क वसूलते हैं।

मैकलॉयड: एनसीएलटी कितना व्यावहारिक!

अभिषेक रक्षित और ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 25 दिसंबर

तीन वित्तीय कर्जदाता कंपनियों येस बैंक, टेक्नो इलेक्टिक ऐंड इंजीनियरिंग और आईएलऐंडएफएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड ने बी एम खेतान ग्रुप तथा मैकलॉयड रसेल कंपनी के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में याचिका दायर की है। वित्तीय कर्जदाताओं ने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) की धारा 7 के तहत न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई है। धारा 7 कर्जदाता कंपनियों को कर्ज लेने वाले कारोबारी द्वारा डिफॉल्ट करने की स्थिति में कारोबारी के खिलाफ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देती है।

मैकलॉयड अभी तक एनसीएलटी में नहीं पहुंची और इस मामले पर अगले महीने सुनवाई होनी है। इस बात की भी संभावना है कि एक समाधान भी प्रस्तुत किया जाए या वित्तीय कर्जदाताओं के साथ कर्ज पुनर्गठन योजना पर चर्चा की जाए। हालांकि अगर इस मामले को स्वीकृति मिल जाती है और आईबीसी के तहत कंपनी के शीर्ष स्तर में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो इसके आकार के चलते बहुत अधिक खरीदार मिलने की संभावना नहीं है।

भारत की सबसे बड़ी चाय कंपनी मैकलॉयड द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 21 चाय बागान बेचने के बाद भी कंपनी के पास भारत में 5.5-5.8 करोड़ किलोग्राम मात्रा उपलब्ध है। विदेशी कारोबार से इसमें 2.6 करोड़ किलोग्राम मात्रा और जुड़ जाती है जिसके चलते कंपनी का कुल उत्पादन करीब 8.1-8.4 करोड़ किलोग्राम हो जाता है।

म्युचुअल फंडों को अभी नहीं भा रहे इनविट

अमृता पिल्लई और जश कृपलानी
मुंबई, 25 दिसंबर

इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) को भारत में जारी किए दो वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन म्युचुअल फंडों को अभी यह विकल्प पूरी तरह रास नहीं आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा इनविट जारी किए जाने की संभावना से इसे लेकर उम्मीद बढ़ी है कि अब रुझान में बदलाव आ सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नवंबर 2019 के आंकड़े के अनुसार, म्युचुअल फंडों द्वारा इनविट में लगाई गई पूंजी 933 करोड़ रुपये है।

केयर रेटिंग्स के सहायक निदेशक (समूह प्रमुख, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं परियोजना वित्त) रत्नम राजू ने कहा, 'म्युचुअल फंडों ने अब तक इनविट में बड़ा निवेश नहीं किया है।' अब तक दो इनविट सूचीबद्ध हुए हैं - आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का आईआरबी इनविट फंड और स्टरलाइट पावर का इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज के दो फाइबर एवं टावर इनविट और एलऐंडटी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (आईडीपीएल) इंडइन्फ्राविट निजी तौर पर पेश किए गए।

ब्लूओसन कैपिटल एडवायजर्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी निपुन मेहता ने कहा, 'शुरुआती दिनों में, म्युचुअल फंड इनविट में निवेश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इसके लिए मंजूरी नहीं दी गई थी। अब स्थिति बदल गई है।' उन्होंने कहा, 'अब लगभग सभी फंडों को जरूरी मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि हम उन्हें क्रेडिट रिस्क फंडों में निवेश करते क्यों नहीं देख सकते। इन फंडों के लिए वाईटीएम (परिपक्वता पर प्रतिफल) इनविट द्वारा मुहैया कराए जाने वाले प्रतिफल की तुलना में कम है, जिससे फंडों के लिए यह अच्छा निवेश विकल्प बन गया है।'

कुछ फंड हाउस क्रेडिट रिस्क फंडों के लिए खुदरा निवेशकों में दिलचस्पी के अभाव को जिम्मेदार मान रहे हैं। एक फंड हाउस के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'इन योजनाओं को दीर्घावधि पूंजी की जरूरत होती है, लेकिन क्रेडिट रिस्क फंड जैसे दीर्घावधि फंडों में खुदरा निवेशकों की दिलचस्पी कमजोर हुई है। अल्पावधि फंडों में आने वाली पूंजी का इस्तेमाल इन निवेश योजनाओं में नहीं किया जा सकता।'

इलस्ट्रेशन: अजय मोहंती

बीएसई के आंकड़े के अनुसार, आईआरबी के इनविट फंड की यूनिट में म्युचुअल फंडों की 11 प्रतिशत की भागीदारी है। वहीं स्टरलाइट के इनविट में म्युचुअल फंडों का योगदान महज 1 प्रतिशत पर है।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक सचिन गुप्ता का कहना है कि म्युचुअल फंड डेट-आधारित फंडिंग से भी दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा, 'डेट के संदर्भ में, फंडों ने अब तक बड़ा निवेश नहीं किया है। कई इनविट डेट के 10 वर्षों से अधिक की अवधि पर केंद्रित हैं, जबकि म्युचुअल फंड संक्षिप्त अवधि पर ध्यान दे सकते हैं।'

अच्छी जमीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का दांव

गोदरेज समूह की रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट में 3,000 करोड़ रुपये की नकदी है

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 25 दिसंबर

गोदरेज समूह की रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छी जगहों पर जमीन खरीदने पर विचार कर रही है, डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट में खुद की पूंजी का निवेश कर रही है।

इस साल जून में कंपनी ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 2,100 करोड़ रुपये जुटाए, जो इस साल इसके जरिए रकम जुटाने वाली दूसरी रियल एस्टेट डेवलपर है।

इस महीने कंपनी ने नवी मुंबई में हाउसिंग परियोजना विकसित करने के लिए स्थानीय डेवलपर के साथ संयुक्त उद्यम की घोषणा की है, जहां 100 एकड़ जमीन पर 76 लाख वर्गफुट की परियोजना विकसित की जाएगी। विकसित होने वाला इलाका मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स का तीन चौथाई होगा। कंपनी ने इस महीने तीन और परियोजनाओं का ऐलान किया है।

बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए साक्षात्कार में कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, हम अच्छी गुणवत्ता वाली और जमीन के बड़े टुकड़े पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। एकमात्र हमारी कंपनी ही ऐसा कर सकती है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इससे पहले मुंबई के चेंबूर इलाके में 150 करोड़ रुपये में आरके स्टूडियो का अधिग्रहण किया और इस पर प्रीमियम परियोजना बना रही है। कंपनी ने ओंकार रियल्टर्स ऐंड डेवलपर्स के साथ इस साल संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं जो बांद्रा में लक्जरी हाउसिंग परियोजना बनाने के लिए है, जो मुंबई के पॉश इलाकों में से एक है।

गोदरेज प्रॉपर्टीज की रणनीति इस बाजार में अलग है। एक ओर जहां डेवलपर्स कम पेशकश कर रही है और नकदी के लिए मौजूदा स्टॉक निकाल रही है और बकाया चुका रही है, वहीं गोदरेज की रणनीति अलग है।

साल 2019 में नए आवासीय पेशकश में 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह साल 2018 के 1,59,452 फ्लैट के मुकाबले 1,26,998 फ्लैट रह गया। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में नई पेशकश 31 फीसदी घटकर 26,405 इकाई रह गई और कुल गिरावट में बड़ा योगदान किया। यह जानकारी कंसल्टेंसी जेएलएल से मिली।

मल्होत्रा ने कहा, आज जमीन की कीमत रियल एस्टेट के शानदार दिनों के मुकाबले 40-50 फीसदी कम है यानी ये जमीन 40-50 फीसदी छूट पर मिल रहे हैं। बड़े सौदे करने में कंपनी को नकदी से मदद मिल रही है, जो उसके पास है। साथ ही मजबूत ब्रांड का भी फायदा मिल रहा है।

मल्होत्रा ने कहा, हमारे पास बैलेंस शीट में 3,000 करोड़ रुपये नकद हैं। हम अगले दो से तीन साल में 5,000 करोड़ रुपये से लेकर 6,000 करोड़ ररुपये की नकदी लगाएंगे।

पिछले महीने कंपनी के चेयरमैन पिरोजशॉ गोदरेज ने कहा कि वह साल की बाकी अवधि में 13-14 नए प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं, जो कंपनी के लिए रिकॉर्ड है।

मल्होत्रा ने कहा, कंपनी डेवलपमेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का नया वर्जन ला रही है, जहां वह परियोजना की जमीन का 50 फीसदी निवेश करती है। इसमें वह शुल्क लगा सकती है और नहीं भी लगा सकती है। सामान्य डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी अपना नाम सामने रखती है, निर्माण करती है और परियोजना के राजस्व के 12-15 फीसदी के बराबर शुल्क लेकर विपणन करती है।

उन्होंने कहा, डेवलपमेंट मैनेजमेंट वहां काम करता है जहां साझेदारों की बैलेंस शीट मजबूत होती है। आज बहुत ज्यादा साझेदार मौजूद नहीं हैं जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो। इसी वजह से हम जमीन में खुद की पूंजी का निवेश करते हैं। पुणे में कंपनी ने एक सौदा किया है जहां डेवलपमेंट मैनेजमेंट नए मॉडल के तहत है और इसमें कंपनी 2.5 करोड़ वर्गफुट विकसित करेगी।

बड़ी परियोजनाओं पर भी कंपनी की नजर

- जून में कंपनी ने पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 2,100 करोड़ रुपये जुटाए, जो इस साल इसके जरिए रकम जुटाने वाली दूसरी रियल एस्टेट डेवलपर है
- इस महीने कंपनी ने नवी मुंबई में हाउसिंग परियोजना विकसित करने के लिए संयुक्त उद्यम की घोषणा की है, जहां 100 एकड़ जमीन पर 76 लाख वर्गफुट की परियोजना विकसित की जाएगी
- गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इससे पहले मुंबई के चेंबूर इलाके में 150 करोड़ रुपये में आरके स्टूडियो का अधिग्रहण किया और इस पर प्रीमियम परियोजना बना रही है
- कंपनी डेवलपमेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट का नया वर्जन ला रही है, जहां वह परियोजना की जमीन का 50 फीसदी निवेश करती है

भारत बॉन्ड ईटीएफ में अतिरिक्त आवेदन स्वीकार करेगी सरकार

तीन साल और 10 साल की सीरीज में इश्यू के आधारभूत आकार के मुकाबले अतिरिक्त बोलियां मिलीं

जश कृपलानी
मुंबई, 25 दिसंबर

सरकार ने भारत बॉन्ड ईटीएफ में तीन साल और 10 साल की सीरीज में मिले अतिरिक्त आवेदन स्वीकार करने का फैसला लिया है। तीन साल वाली श्रेणी में 6,982 करोड़ रुपये के आवेदन मिले जबकि इश्यू का मूल आकार 3,000 करोड़ रुपये का था, यानी उसे 2.3 गुना आवेदन मिले। इसी तरह 10 साल वाली श्रेणी में 5,413 करोड़ रुपये के आवेदन मिले जबकि इश्यू का मूल आकार 4,000 करोड़ रुपये का था। इस तरह से इस श्रेणी में 1.4 गुना आवेदन मिले।

करीब 55,000 करोड़ आवेदन मिले और इसमें खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली और डिजिटल चैनल का भारी सहारा मिला।

यह ईटीएफ 12 दिसंबर को खुला। पहले दिन संस्थागत निवेशकों ने एंकर बुक के लिए भागीदारी की। बाजार के सूत्रों के मुताबिक, सार्वजनिक व निजी बैंकों के अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम समेत अन्य बीमा कंपनियों ने ईटीएफ की एंकर बुक में भागीदारी की।

डीमैट खाते के बिना निवेशकों को इसमें निवेश के लिए ईटीएफ की पेशकश एडलवाइस एएमसी ने फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर के जरिए की।

सूत्रों ने कहा कि ईटीएफ में प्रवासी भारतीय निवेशकों, धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई), बड़ी कंपनियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली।

चूंकि प्रबंधन शुल्क निवेशक की परिसंपत्ति का 0.0005 फीसदी रखा गया था, लिहाजा इस पर सवाल उठ रहे हैं कि वितरण लागत को कैसे समाहित किया जाएगा। एडलवाइस एएमसी ने अन्य चैनल के अलावा पेटीएम मनी, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, जीरोधा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ईटीएफ के वितरण में किया।

अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना की सफलता के बाद सरकार एएए रेटिंग वाले पीएसयू बॉन्ड को ईटीएफ का हिस्सा बनाने पर विचार कर सकती है। एक सूत्र ने कहा, अभी एएए रेटिंग वाले बॉन्ड को शामिल किया गया है ताकि खुदरा निवेशकों का इसपर भरोसा हो सके।

- करीब 55,000 करोड़ आवेदन मिले और इसमें खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी देखने को मिली
- ईटीएफ में प्रवासी भारतीय निवेशकों, धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई), बड़ी कंपनियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी रही

बॉम्बे शेविंग कंपनी ने कोलगेट पामोलिव व अन्य से जुटाए 45 करोड़ रुपये

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 25 दिसंबर

बॉम्बे शेविंग कंपनी ने सिक्स्थ सेंस वेंचर पार्टनर्स की अगुआई में दूसरे दौर की फंडिंग के तहत 45 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मौजूदा निवेशक कोलगेट पामोलिव एशिया पैसिफिक (कोलगेट पामोलिव की सहायक) ने भी इस दौर की फंडिंग में हिस्सा लिया। कंपनी ने कहा कि 30 ऐंजल व शुरुआती कर्मचारियों के लिए 20 करोड़ रुपये की निकासी का मौका भी सृजित किया है। इस फंडिंग के साथ ही बॉम्बे शेविंग कंपनी ने कुल 80 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं।

बॉम्बे शेविंग कंपनी के संस्थापक व सीईओ शांतनु देशपांडे ने कहा, इस यात्रा में सिक्स्थ सेंस को पाकर हम उत्साहित हैं। यह अग्रणी कंज्यूमर फंड है और यह हमारे लिए मूल्यवान है। हम ज्यादा रकम के निवेश पर विश्वास नहीं करते, हालांकि ऐंजल व शुरुआती कर्मचारियों के लिए निकासी का मौका काफी सकारात्मक नतीजा है। संपत्ति सृजन ही हमें आगे बढ़ा रहा है।

साल 2016 में बॉम्बे शेविंग कंपनी की शुरुआत प्रीमियम शेविंग के साथ हुई और जल्द ही कंपनी ने स्किन, बेयर्ड व स्नान प्रसाधन की श्रेणी में विस्तार कर लिया। फर्म अपने उत्पाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचती है और उसके पास 45 एसकेयू (स्टॉक कीपिंग यूनिट्स) से ज्यादा का पोर्टफोलियो है, जो शेविंग, स्नान प्रसाधन, स्किन आदि की श्रेणी में है।

फर्म की योजना ताजा रकम का इस्तेमाल ब्रांड बनाने, स्किनकेयर श्रेणी में अपनी मौजूदगी का विस्तार करने और शेविंग में और आगे बढ़ने पर करने का है। कंपनी ऑफलाइन के जरिए अपनी मौजूदगी आगामी महीनों में 3,000 से 10,000 स्टोर कर करने पर ध्यान देगी। बॉम्बे शेविंग कंपनी के पास अभी 2.5 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं और उसका इरादा अगले 12-15 महीनों में 100 करोड़ रुपये का ब्रांड बनने का है।

टीसीएस के पूर्व वाइस चेयरमैन सुब्रमण्यन रामादोरई और मैकिंजी ऐंड कंपनी के 16 साझेदार साल 2016 में बॉम्बे शेविंग कंपनी को समर्थन देने वाले ऐंजल निवेशकों में शामिल थे।

- इस फंडिंग के साथ ही बॉम्बे शेविंग कंपनी ने कुल 80 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं
- बॉम्बे शेविंग कंपनी के पास अभी 2.5 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं

पिटे हुए शेयरों में निवेशकों ने गंवाए 5 लाख करोड़ रु.

सुंदर सेतुरामन
मुंबई, 25 दिसंबर

बेंचमार्क सूचकांक भले ही नई ऊंचाई को छू गए हैं, लेकिन 1,300 शेयरों में इस साल अब तक 35 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है और इस तरह से इस अवधि में निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो गए।

मुख्य सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में इस साल अब तक क्रमश: 15 फीसदी व 13 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जिन कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में भारी गिरावट दर्ज हुई है उनमें येस बैंक, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस, ज़ी एंटरटेनमेंट, वोडाफोन आइडिया और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स शामिल हैं।

बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक, बाजार के कमजोर हालात को देखते हुए बिकवाली काफी तेज रही है, यहां तक कि कंपनी संचालन से जुड़े मामूली संकेत या कर्ज चुकाने में अक्षमता पर भी। एक विश्लेषक ने कहा, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियों पर चोट पड़ रही है। साथ ही कंपनी प्रशासन से जुड़ी चिंता को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, यहां तक कि लार्जकैप कंपनियां भी बिकवाली के दायरे में आ रही हैं।

पूंजी आवंटन की नीतियां और अल्पांश शेयरधारकों के बजाय प्रवर्तक के हित में लिए गए फैसले से भी सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के शेयर पर भारी चोट पड़ी है। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा, सार्वजनिक उपक्रमों में नकदी का स्तर निवेशकों के आकर्षण का सबसे बड़ा कारण रहा है, लेकिन कमजोर लाभ के बावजूद ज्यादा लाभांश दिए जाने के कारण नकदी तेजी से घट रही है।

विश्लेषकों ने कहा कि कई सार्वजनिक उपक्रमों ने लाभांश भुगतान के लिए अपनी नकदी या संचयी आय का इस्तेमाल किया, जो सरकारी खजाने में इजाफे के लिए जरूरी था।

कुछ बड़ी पीएसयू को जिंस व पूंजीगत खर्च के प्रतिकूल चक्र से झटका लगा।

बड़ी चोट

1,000 से ज्यादा शेयर इस साल अब तक 35 फीसदी से ज्यादा टूट चुके हैं

कंपनी	बाजार पूंजीकरण में नुकसान (करोड़ रु.)	शेयर कीमतों में बदलाव (%)
येस बैंक	-29,363	-72
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस	-23,828	-65
ज़ी एंटरटेनमेंट	-17,379	-38
अरविंदो फार्मा	-15,392	-36
वोडाफोन आइडिया	-14,542	-72
आईआईएफएल फाइनैंस	-11,517	-44
बीएचईएल	-11,445	-39

संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो
स्रोत : कैपिटालाइन, एक्सचेंज

डिजिटल भुगतान व 5जी फोन पर रहेगी वनप्लस की नजर

युवराज मलिक
बेंगलूर, 25 दिसंबर

चीन की स्मार्टफोन निर्माता वनप्लस डिजिटल भुगतान के साथ साथ 5जी आधारित फोन पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने की संभावना तलाश रही है।

हालांकि कंपनी भारत से बाहर निर्मित 5जी फोन का निर्यात अपने कुछ वैश्विक बाजारों में पहले से ही कर रही है, लेकिन अब वह अगले साल भारत में मोबाइल भुगतान प्रणाली शुरू करने की तैयारी कर रही है।

भारत में वनप्लस के महा प्रबंधक विकास अग्रवाल ने कहा, 'अगले साल भुगतान के साथ साथ 5जी फोन पर हमारा खास जोर रहेगा। हम अमेरिका, यूरोप और चीन में 5जी फोन पहले ही पेश कर चुके हैं और अब भारत में भी इसे जल्द पेश किया जाएगा।'

भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन श्रेणी में अच्छी बाजार भागीदारी रखने वाली वनप्लस वर्ष 2020 के शुरू में 'वनप्लस पे' शुरू करने की तैयारी कर रही है।

वनप्लस टीवी की तरह कंपनी की भुगतान सेवा शुरू में सिर्फ भारत में पेश की जा सकती है। इससे वनप्लस को पेमेंट ऐप की सेवा मुहैया करा रहीं गूगल, पेटीएम और व्हाट्सऐप से मुकाबला करने में मदद मिलेगी। लेकिन ऐप व्यवसाय के विपरीत, वनप्लस पे में ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराए जाने की संभावना है, क्योंकि वह अपने स्वयं के हार्डवेयर से संपन्न है।

सेबी के लिए नए पूर्णकालिक सदस्य की तलाश शुरू

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

केंद्र सरकार ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिए नए पूर्णकालिक सदस्य की तलाश शुरू कर दी है जबकि सरकार ने अभी यह फैसला भी नहीं लिया है कि मौजूदा चेयरमैन अजय त्यागी को सेवा विस्तार दिया जाएगा या नहीं।

त्यागी का कार्यकाल 28 फरवरी, 2020 को पूरा हो रहा है और पूर्णकालिक सदस्य एम पुरी बुच अपना तीन साल का कार्यकाल 4 अप्रैल, 2020 को पूरा कर रही हैं।

16 दिसंबर को जारी अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के लिए आवेदन आमंत्रित किया है, जिसके लिए आखिरी तारीख 27 जनवरी है। हालांकि मंत्रालय ने यह नहीं बताया है कि कितने पद खाली हैं। अभी सेबी के चार पूर्णकालिक सदस्य हैं। अन्य तीन पूर्णकालिक सदस्यों का कार्यकाल 2021 में पूरा होगा। बुच कुछ प्रमुख इकाइयों मसलन बाजार नियमन, निगरानी, आर्थिक व नीति विश्लेषण और सूचना प्रौद्योगिकी का कामकाज संभाल रही हैं। इससे पहले बुच न्यू डेवलपमेंट बैंक शांघाई में कंसल्टेंट थीं। वह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी का पदभार संभाल चुकी हैं और वह आईसीआईसीआई बैंक के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक भी रह चुकी हैं। बुच की नियुक्ति अपनी तरह की पहला मामला है जब एक महिला को बाजार नियामक सेबी में अहम पद के लिए चुना गया। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, यह नियुक्ति अधिकतम पांच साल के लिए या 65 साल पूरा तक के लिए (जो भी पहले हो) होगी। सदस्य के पास भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव को बराबर वेतन पाने या फिर हर महीने 3.75 लाख रुपये एकीकृत वेतन पाने का विकल्प होगा। इसके अलावा वह दोबारा नियुक्ति के भी पात्र होंगे। नियुक्ति की ऐसी ही शर्तें चेयरमैन के लिए भी लागू होती है। चेयरमैन को भारत सरकार के सचिव के बराबर वेतन या 4.5 लाख रुपये प्रति माह एकीकृत वेतन का विकल्प दिया गया है।

मंत्रालय ने कहा है, यह नियुक्ति केंद्र सरकार वित्तीय क्षेत्र की नियामकीय नियुक्ति खोज समिति (एफएसआरएएससी) की सिफारिशों पर होगी। एफएसआरएएससी योग्यता के आधार पर (जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन न भी किया हो) किसी अन्य व्यक्ति की पहचान करने और उसके नाम की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र है।

नई दिल्ली | 26 दिसंबर 2019 गुरुवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

भारत में बढ़ी विदेशी बैंकों की मौजूदगी

निधि राय
मुंबई, 25 दिसंबर

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट 'ट्रेंड्स ऐंड प्रोग्रेस आफ बैंकिंग इन इंडिया 2018-19' में कहा है कि भारत में विदेशी बैंकों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बैंकों की शाखाओं की संख्या सालाना आधार पर 286 से बढ़कर 299 हो गई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'रिजर्व बैंक ने दो विदेशी बैंकों एसबीएम बैंक और डीबीएस बैंक को क्रमश: 6 दिसंबर, 2017 और 4 अक्टूबर, 2018 को लाइसेंस जारी करक 1 दिसंबर, 2018 और 1 मार्च ,2019 से परिचालन करने की अनुमति दी। यह मुख्य रूप से डीबीएस बैंक द्वारा अतिरिक्त शाखाएं खोलने को लेकर था, जिससे इसे शाखा से बदलकर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई (डब्ल्यूओएस) बनाया जा सके।'

भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट आई

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विदेशी जमीन पर मौजूदगी के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत के सरकारी बैंक शाखाएं व अन्य कार्यालय घटाकर धीरे धीरे विदेश में अपनी मौजूदगी घटा रहे हैं, जिससे लागत कम की जा सके। साथ ही एक ही शहर या आसपास के शहरों की शाखाएं अव्यावहारिक शाखाएं बंद कर उन्हें तार्किक बनाया जा रहा है। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थिति कुल मिलाकर स्थिर बनी हुई है।'

विदेशी बैंकों की पूंजी मार्च 2019 में बढ़कर 77,809 करोड़ रुपये हो गई, जो मार्च 2018 में 67,883 करोड़ रुपये थी। इसमें 15 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। विदेशी बैंकों की उधारी मार्च 2019 में बढ़कर 1,51,367 करोड़ रुपये हो गई, जो मार्च 2018 में 1,27,690 करोड़ रुपये थी। इसमें 18 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। विदेशी बैंकों के जमा में भी 17 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और यह मार्च 2019 में 5,81,857 करोड़ रुपये हो गई, जो मार्च 2018 में 4,94,901 करोड़ रुपये थी।

एआरसी द्वारा खरीदा खराब कर्ज बढ़ा

अभिजित लेले
मुंबई, 25 दिसंबर

संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसी) द्वारा गैर निष्पादित कर्ज की मात्रा जून 2019 के पहले के 12 महीने में 17.4 प्रतिशत बढ़कर 3.8 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

बहरहाल जून 2019 तक कुल एनपीए में 12 प्रतिशत की कमी आई है। जून 2019 को समाप्त एक साल की अवधि के दौरान एआरसी ने 57,506 करोड़ रुपये खराब कर्ज खरीदा है, जो जून 2018 में समाप्त वर्ष के 67,830 करोड़ रुपये की तुलना में कम है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के मुताबिक एआरसी द्वारा भुनाई गई प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) जून 2019 में बढ़कर 12,906 करोड़ रुपये हो गईं, जो जून 2018 में 8,830 करोड़ रुपये थीं। यह उन निवेशकों द्वारा किया गया भुगतान है, जिन्होंने एसआर में निवेश किया था। रिजर्व बैंक ने 24 दिसंबर 2019 को भारत में बैंकिंग क्षेत्र की 2018-19 में प्रगति पर रिपोर्ट जारी की है।

जून 2019 में बकाया एसआर बढ़कर 1,14,615 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 98,118 करोड़ रुपये था। कानूनी व्यवस्था के तहत वसूली को भेजे गए मामले बढ़े हैं, ऐसे में दबाव वाली संपत्तियां एआरसी को बेचकर बैलेंस शीट साफ की गई है और सालाना आधार पर जीएनपीए का अनुपात कम हुआ है।

बहरहाल एआरसी की अधिग्रहण लागत संपत्ति की बुक वैल्यू के अनुपात में बढ़ी है। इससे संकेत मिलता है कि बैंकों को इन बिक्री से मामूली लाभ मिला है।

एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में बैंकों के सब्सक्रिप्शन की हिस्सेदारी घटकर जून 2019 के अंत तक 69.5 प्रतिशत रह गई, जो एक साल पहले 79.8 प्रतिशत थी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह एसआर में निवेश घटाने और निवेश आधार के विविधीकरण के एजेंडे के अनुरूप है।

औषधि मूल्य नीति पर हो रहा विचार

सोहिनी दास
मुंबई, 25 दिसंबर

दवा के दाम में बदलाव को लेकर बढ़ रहे हैं न्यायालय में मामले

- कंपनियों की लंबे समय से मांग है कि दवा के दाम में बदलाव उस दवा के अगले बैच के उत्पादन से लागू हो
- दवाओं के दाम घटने पर बाजार में विभिन्न स्तर पर पहुंच चुकी दवाओं को वापस मंगाकर उस पर फिर से मूल्य अंकित करना श्रमसाध्य
- इस नियम से बढ़ रही हैं याचिकाएं, हो रही है कंपनियों को मुसीबत
- इस समस्या के समाधान पर एनपीपीए कर रहा है विचार
- बिक्री श्रृंखला के स्तर पर भी दवा के दाम घटाने के विकल्प पर विचार

दवा विनिर्माताओं की ओर से दवाओं के दाम तय करने संबंधी किसी भी बदलाव को दवा के अगले बैच से लागू करने की लंबे समय से जारी मांग की सरकार समीक्षा कर रही है।

ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। अगर प्राधिकरण को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 (डीपीसीओ 2013) में संशोधन की जरूरत महसूस होती है तो उस पर फैसला करेगा।

अगर ऐसा फैसला लागू किया जाता है तो इससे दवा कंपनियों द्वारा ज्यादा मूल्य वसूले जाने के मामलों में बहुत ज्यादा कमी आएगी। अहमदाबाद के एक दवा विनिर्माता ने कहा, 'दवाओं के ज्यादा दाम वसूलने के तमाम मामले आते हैं क्योंकि दवा विनिर्माता सभी दवाइयां वापस मंगाने और उस पर नया मूल्य लिखने में सक्षम नहीं होते। इस तरह से उस बैच की बाजार में पहुंच चुकी दवाओं के दाम पुनरीक्षित होकर कम नहीं हो पाते।'

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि उद्योग ने संशोधन का अनुरोध किया है, जिससे कि उन्हें अगले बैच के दवा उत्पादन पर मूल्य में बदलाव की अनुमति मिल सके। उन्होंने कहा, 'हमने इस पर विचार किया है। अब एनपीपीए इसकी समीक्षा कर रहा है। हम इस मसले पर संतुलित फै सला करेंगे क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर की दरों में बदलाव को भी तत्काल लागू किया जाना है।'

इस समय औषधि मूल्य नियामक एनपीपीए आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनईएलएम) के तहत दवा के मूल्य एक साल के लिए तय करता है। एनईएलएम के तहत आने वाली दवाओं के दाम या तो बढ़ती हैं, या घटती हैं। यह थोक मूल्य सूचकांक पर निर्भर होता है। सीलिंग मूल्य की भी नियामक समय समय पर समीक्षा करता है। कीमतें बाजार भाव आधारित फॉर्मूले से तय होती हैं, जिसमें बाजार में सभी दवाओं के औसत मूल्य (जिनकी बाजार हिस्सेदारी कम से कम 1 प्रतिशत होती है) पर विचार किया जाता है।

ऐसे समय में जब सीलिंग मूल्य कम किया जाता है, दवा विनिर्मातओं को लॉजिस्टिक्स समस्याओं से जूझना पड़ता है। उन्हें बाजार में पहुंच गई दवाएं वापस मंगानी होती हैं और उसके बाद उनके दाम फिर से लिखकर बाजार में वापस भेजना होता है। ऐसा न करने पर सरकार ने दवा विनिर्माताओं पर जुर्माने का प्रावधान किया है, क्योंकि वह दवाएं एनपीपीए द्वारा तय मूल्य से ज्यादा दाम पर बिकती हैं। अगर कीमतें बढ़ती हैं तो ज्यादा दाम लेने का मामला नहीं होता है।

इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपनाथ चौधरी ने कहा, 'कीमतों में बदलाव अगले बैच से लागू किया जाना चाहिए। इससे नियम लागू करना आसान होगा और इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कीमतें तय किए जाने पर अनावश्यक विवाद नहीं होंगे।' उन्होंने कहा कि यह लॉजिस्टिक्स के हिसाब से कठिन होता है कि उन दवाओं के दाम घटाए जाएं जो कारोबार के विभिन्न स्तर पर देश भर के बाजार में पहुंच चुकी हैं।

एक अन्य सरकारी अधिकारी ने कहा कि 'विवादों से बचने का एक तरीका यह है कि दवा विनिर्माता दवाओं के दाम अपनी वेबसाइट पर थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए अद्यतन कर दे और उसके बाद वितरण तंत्र यह दवाओं के दाम घटाना सुनिश्चित करे और वे नए दाम पर बेची जाएं।' इससे लॉजिस्टिक्स समस्या दूर होगी और दवाएं वापस मंगाने और उनकी फिर से पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं होगी।

बहरहाल उद्योग इस बात को लेकर निश्चिंत नहीं है कि यह व्यवस्था कितनी कारगर होगी। एक मझोले आकार की दवा कंपनी के एक अधिकारी ने कहा, 'हर खुदरा कारोबारी को इलेक्ट्रॉनिकली सूचित करना आसान नहीं है। हमें समाधान निकालना होगा।'

बहरहाल सरकार सक्रियता से विकल्पों पर विचार कर रही है। इसमें एकमुश्त समाधान, दवा कंपनियों से वसूली करना, जिन्होंने कथित रूप से दवा के ग्राहकों से मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के तहत ज्यादा पैसे लिए हैं, शामिल है। बकाया अब बढ़कर 5,476.9 करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें से 4,032.5 करोड़ रुपये के मामले याचिकाओं में फंसे हैं। पिछले तीन साल में वसूली बहुत मामूली है। जून 2019 में दवाओं के ज्यादा दाम लेने के मामले 2,038 थे।

डिजिटल मीडिया में एफडीआई पर आएगी सफाई

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जल्द डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। कुछ अंशधारकों ने सरकार के डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। इस उद्योग की कंपनियों और विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल मीडिया क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 26 प्रतिशत रखने से कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। इनमें से कई कंपनियां कोष जुटाने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन 26 प्रतिशत की सीमा उन्हें दिक्कत हो रही है। *भाषा*

बैंकों के विलय से ढीली पड़ेगी डिजिटल पहल

देवाशीष महापात्र
बेंगलूरु, 25 दिसंबर

विलय की प्रक्रिया से गुजर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबीध के डिजिटल बैंकिंग की पहल ढीली पड़ सकती है। इसकी वजह कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म के एकीकरण में देरी है। इस मामले से जुड़े बैंक अधिकारियों का कहना है कि जिन बैंकों विलय हो रहा है, वे एक ही कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) पर काम करते हैं, लेकिन इनके वर्जन में अंतर है और पूरी तरह से इसके एकीकरण में 18 महीने लग सकते हैं।

डिजिटल बैंकिंग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'डिजिटल बैंकिंग में एपीआई (ऐप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) को सीबीएस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जिससे बाधारहित परिचालन हो सके। इसकी वजह है कि ग्राहकों के सभी आंकड़े इस प्लेटफॉर्म पर हैं। जब तक इन सीबीएस प्लेटफॉर्मों का विलय जाएगा, एकीकरण के पहले कोई नया उत्पाद आने का प्रश्न ही नहीं है।' उन्होंने कहा, 'अगर कोई नया एपीआई पेश होता है तो बैंक को इसे अपने सीबीएस से जोड़ना होगा और बाद में इसे हटाना होगा। यह ऐप्लीकेशन की क्षमता पर निर्भर होगा।'

तत्काल खाता खोलने, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और वर्चुअल वेलकम किट के साथ कुछ अन्य सेवाएं डिजिटल बैंकिंग पहल के तहत आती हैं। हालांकि कुछ सरकारी बैंकों ने इन ऐप आधारित प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नए ग्राहकों को कर्ज देना शुरू कर दिया है। विलय की प्रक्रिया में शामिल एक और अधिकारी ने कहा, 'हमें एक ही सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कई एपीआई का एक ऐप्लीकेशन में विलय करना होगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम दोनों बैंकों के फीचर का मूल्यांकन कर रहे हैं।'

सरकारी बैंकों के एकीकरण की योजना के तहत केंद्र सरकार ने अगस्त में इन बैंकों के विलय की घोषणा की थी। इससे सरकारी बैंकों की संख्या पहले के 27 से घटकर 12 रह जाएगी।

यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक आफ कॉमर्स का विलय पंजाब नैशनल बैंक में किया जाएगा, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक के साथ होगा। इसी तरह से इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ मिलाया जाएगा, जबकि आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का वियल यूनियन बैंक आफ इंडिया में होगा।

विलय योजना के फैसले में टेक्नोलॉडी प्लेटफार्म ने अहम भूमिका निभाई है और बैंक अधिकारियों का कहना है कि विलय वाले बैंक एक ही कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, इसके बावजूद विलय में जटिलता ज्यादा है। उदाहण के लिए केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक ओराकल के आई-फ्लेक्स पर काम करते हैं, लेकिन दोनों के सॉफ्टवेयर का वर्जन अलग अलग है। सिंडिकेट बैंक जहां लेटेस्ट वर्जन (11.6) इस्तेमाल कर रहा है, वहीं केनरा बैंक 10.2 वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से यूनियन बैंक, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, इन्फोसिस फाइनैंस के अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल करते हैं।

एमएसएमई के लिए बन सकता है कोष

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

नहीं मिलेगा अतिरिक्त धन

- नोटबंदी की मार और नकदी संकट से अभी भी जूझ रहे हैं देश के छोटे कारोबारी
- भारतीय रिजर्व बैंक की समिति ने एसएमई के लिए 500 करोड़ रुपये के स्ट्रेस्ड असेट फंड का सुझाव दिया था
- प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके लिए धन मुहैया कराने के बजाय मंत्रालय को योजनाएं तार्किक बनाने का सुझाव दिया
- अब एसएमई मंत्रालय अपनी मौजूदा महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम सहित योजनाओं में कटौती कर धन जुटाने की कर रहा है कवायद

सरकार छोटे उद्यमों के लिए 5000 करोड़ रुपये के स्ट्रेस्ड ऐसेट फंड के गठन को मंजूरी दे सकती है। इसका सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक की समिति ने दिया है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि वित्तीय स्थिति ठीक न होने की वजह से केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की मौजूदा योजनाओं में कटौती कर ऐसा कर सकती है।

जून में एमएसएमई पर बनी यूके सिन्हा समिति ने नोटबंदी के असर और नकदी संकट से जूझ रहे छोटे उद्यमों के लिए व्यापक एमएसएमई सुधारों व फंड बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन धन की उपलब्धता न होने की वजह से इस योजना को लागू करने में देरी हो रही है। इस मामले में एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सितंबर की शुरुआत में कहा था कि सरकार सिफारिशों को 15 दिन के भीतर लागू करेगी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'बातचीत चल रही है और सरकार यह देखेगी कि धन का उपयोग किस तरह होगा और वे मानक क्या होंगे, जिनके आधार पर फर्म को दबाव वाली फर्म के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एमएसएमई मंत्रालय से कई बार कहा है कि वह योजना की व्यावहारिकता का आकलन करे। एमएसएमई मंत्रालय के सूत्रों ने साफ किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहल को लागू करने के लिए जरूरी अतिरिक्त वित्तपोषण का वादा नहीं किया और इसकी जगह पर यह देखने को कहा कि मौजूदा योजनाओं को किस तरह तार्किक बनाया जा सकता है। अब मंत्रालय के पास अपनी सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सहित अपनी मौजूदा योजनाओं में कटौती करने का ही विकल्प बचा है।

संभावित कटौती

मंत्रालय के आंकड़ों को बिजनेस स्टैंडर्ड ने देखा है। पीएमईजीपी के माध्यम से पंजीकृत नए एमएसएमई की संख्या 2018-19 में बढ़कर 73,427 हो गई है, जो 2017-18 में 48,398 थी। इससे प्रत्यक्ष रोजगार सृजन 5,70,00 हुआ, जो एक साल पहले 3,87,000 था।

अधिकारी ने कहा, 'यह टिकाऊ रोजगार सृजन है, जहां खासकर ग्रामीण इलाकों में कारोबारी झटकों का स्तर तुलनात्मक रूप से कम है और वृद्धि की संभावना ज्यादा है।'

मंत्रालय के अध्ययन के मुताबिक इस समय जो इकाइयां स्थापित हो रही हैं उनका औसत निवेश 96,000 रुपये है। औसतन एक इकाई में 7.62 लोगों को रोजगार मिलता है।

गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के मकसद से पीएमईजीपी के तहत विनिर्माण इकाई को केंद्र से 25 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है। मंत्रिमंडल ने इनके लिए दूसरी बार 1 करोड़ रुपये तक कर्ज देने को मंजूरी दे दी है, जिन पर अधिकतम ब्याज दर 15 प्रतिशत सालाना होगा। वरिष्ठ सूत्रों ने कहा कि यह कर्ज उन इकाइयों को मिलता है, जो समय से भुगतान कर देती हैं।

उन्होंने कहा कि नए नियम लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

मंत्रालय ने 400 एमएसएमई क्लस्टर स्थापित करने की योजना बनाई है, जो विनिर्माण व सेवा क्षेत्र के लिए होंगे। यह पिछले साल के 98 की तुलना में ज्यादा है। नैशनल सैंपल सर्वे (2015-16) के 73वें दौर के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 6.339 करोड़ इकाइयां हैं। इनसे 11.1 करोड़ नौकरियों (ग्रामीण इलाकों में 4.98 करोड़ और शहरी इलाकों में 6.12 करोड़) का सृजन हुआ है।

देश के सभी मौजूदा एसईजेड में मिलेगी अब हर सेक्टर के उद्योगों को जगह

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 25 दिसंबर

- सरकार के इस फैसले से एसईजेड में खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल हो सकेगा, कंपनियां उद्यम लगाने को आकर्षित होंगी
- डेवलपरों के लिए एसईजेड में फंसी जमीन से धन जुटाना होगा आसान

केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है कि अधिसूचित किए गए मौजूदा सभी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को मल्टी सेक्टर एसईजेड माना जाएगा। इससे एक उद्योग के लिए बनाए गए एसईजेड की जमीन अन्य उद्योगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी।

चीन और अमेरिका के बीच चल रहे कारोबारी जंग के बीच यह सुविधा दिए जाने से एसईजेड में ज्यादा नियामकीय बाधाओं के बगैर ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित करने में मदद मिलेगी। उद्योग जगत के और आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि साथ ही डेवलपरों को मौजूदा एसईजेड की बगैर इस्तेमाल वाली जमीन से धन जुटाने में मदद मिलेगी, और नए एसईजेड बनाने की जरूरत नहीं होगी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2006 में संशोधन के बाद सभी मौजूदा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र को मल्टी सेक्टर एसईजेड माना जाएगा, जहां दो या उससे ज्यादा क्षेत्रों के उद्योग अपने परिचालन के साथ वेयरहाउसिंग और कारोबार शुरू कर सकेंगे।

इसके अलावा आईटी और आईटीईएस, बायोटेक या स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर एसईजेड या मुक्त व्यापार वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए न्यूनतम क्षेत्र की जरूरत 50 हेक्टेयर तय किया गया है और कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में 25 हेक्टेयर या इससे ज्यादा तय किया गया है।

आईटी, आईटीईएस, बॉयोटेक या स्वास्थ्य (अस्पतालों को छोड़कर) सेवाओं के एसईजेड स्थापित करने के लिए न्यूनतम क्षेत्र तय नहीं किया गया है, लेकिन न्यूनतम बिल्टअप एरिया को ए श्रेणी के शहरों के लिए 1,0,000 से घटाकर 50,000 वर्गमीटर, बी श्रेणी के शहरों के लिए 50,000 से घटाकर 25,000 वर्गमीटर, सी श्रेणी के शहरों में 25,000 वर्ग मीटर से 15,000 वर्गमीटर कर दिया गया है।

तमिलनाडु सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि नए नियम एसईजेड क्षेत्र के लिए बड़ा बदलाव हैं और यह राज्य सरकार की कवायदों का परिणाम है। राज्य लंबे समय से एक सेक्टर के लिए बने एसईजेड में खाली पड़ी जमीनों की अन्य सेक्टर के उद्योगों के लिए इस्तेमाल को लेकर दबाव बनाता रहा है।

उद्योग जगत का कहना है कि यह संशोधन एसईजेड ऐक्ट 2005 के नियम आने के 13 साल बाद सकारात्मक बदलाव है। इन वर्षों के दौरान उद्योग का परिदृश्य बदला है और टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल या फुटवीयर को छोड़कर हर क्षेत्र के एसईजेड के पर्याप्त लिवाल नहीं थे। इसकी वजह से कुछ एसईजेड में कई एकड जमीन खाली पड़ी है।

बीएस सूडोकू 3622

7								9
	2		6			4	3	
4				7	5			
3			5		9	1	4	
1		9				5		2
	6	5	1		4			3
			9	4				8
	1	8			2		7	
9								5

परिणाम संख्या 3621

4	3	7	5	1	2	8	9	6
1	6	9	3	4	8	5	7	2
5	2	8	6	9	7	1	4	3
8	7	1	2	3	6	4	5	9
2	9	3	7	5	4	6	8	1
6	5	4	1	8	9	2	3	7
9	1	6	4	7	5	3	2	8
7	4	2	8	6	3	9	1	5
3	8	5	9	2	1	7	6	4

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

आसान ★★☆☆☆

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2145/2150, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2200/2250, सरसों 4500/4525, तिल सफेद 9500/9700, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1670,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2150/2160, गेहूं शरबती 2800/2900, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2950/3000

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1435, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1515, फ्लैक 1455, डीएमओ 1048, टरपीन लैस बोल्ड 1555

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1150/1280, खुरपा 1150/1180,चाकू 1150/1265, रसकट 910/930, शक्कर 1300/1330, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3385, सिहोरा 3255, बुंदकी 3290, बुढ़ाना 3370,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3650, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1180/1230, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4600, खल: सरसों 2350/2450, बिनौला 2550/2650, चना छिलका 2050/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2190/2200, मक्की 2250/2275, बाजरा 1870/1875, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3800/3850, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4770/4775,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3850, जौ 2080/2090,

जोधपुर
गेहूं 2075/2100, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7550/7650, बाजरा (गुजरात) 1990/2000, बाजरा (जयपुर) 2000/2010, चना 4250/4350,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)132, राइसब्रान (अखाद्य) 129, खल सरसों 2150, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1300, लाल 1300, कंटीन्यूअस 1380,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7200/8200, अरहर दाल 7500/8000, उड़द साबुत 7650/8600, उड़द धोया 9000/10000, छिलका 8500/9500, दाल मसूर 5700/6200, चनादाल 5200/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5550/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250,चावल 1509 सेला 5150/5250, धान: शरबती 2100/2150, बासमती 1121 धान 2850/2900,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 4000/4025, हरियाणा 3980/4000, राजस्थान 3900/4000, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2550/2650, सरसों खल 2240/2250,

फाजिल्का
गेहूं 2200/2210, सरसों 4525/4550 रुई (प्रति मन): (जे-34) 4050/4100, कपास देशी 5000/5100, कपास नरमा (क्विं.) 5300/5500, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2600/2650,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2180/2190, चावल परमल कच्चा 2500/2550, से ला 2400/2425, मक्की यूपी 2375/2400, बिहार 2475/2500, दाल उड़द छिलका 8800/10600, चना देशी 5150/5250, दाल चना 5400/5600, काबली चना 5000/5900, राजमां चित्रा पुणे 7000/ 8300,चीन 7300/7900,

करनाल
गेहूं दड़ा 2180/2190, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6000/6100,

हिसार
ग्वार 3775/3800, जौ 1775/1780, सरसों 4250/4300, मूंग 6600/6700, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1050/1070, मैदा 1150/1170, देशी घी (एक ली/जार) 380/480, रिफाइंड (टीन) 1510/1540,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4300/4350, खल बिनौला मोटी 2400/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9450/9500, गेहूं 2150/2200, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1950/2000 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 266

अपरिपक्व विचार

नीति आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों मसलन मांस, मछली, मुर्ग और अंडों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरित किया जाए। यह अपरिपक्व विचार है। दस में से चार बच्चे अल्प पोषण की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु तेजी से खराब होने वाली इन वस्तुओं का पीडीएस के व्यापक नेटवर्क के जरिये वितरण करने का विचार समझदारी भरा नहीं लगता। इन उत्पादों को लगातार ठंडा रखना होगा और देश भर की 5 लाख राशन दुकानों में इसकी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये दुकानें उन क्षेत्रों में भी हैं जहां बिजली की आपूर्ति ही सही नहीं है। इन तमाम उचित मूल्य की दुकानों पर मांसाहारी भोजन रखने के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी जो फिलहाल वित्तीय रूप से एक बड़ा बोझ होगी और लॉजिस्टिक्स के स्तर पर भी यह प्रबंधनीय नहीं है। भोजन की गुणवत्ता के साथ किसी तरह का समझौता स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। इससे इस कदम का उद्देश्य ही खारिज हो जाएगा। खाद्य सब्सिडी पहले ही 1.84 लाख करोड़ रुपये (2019-20 के बजट में) से अधिक है। इन महंगे खाद्य पदार्थों को गरीबों की पहुंच में लाने के लिए इसमें भी बहुत अधिक इजाफा करना होगा। दिक्कत यह भी है कि अगर सरकार जरूरी संसाधन जुटाने में सफल हो भी जाती है तो भी कुपोषण की समस्या शायद पूरी तरह दूर नहीं होगी क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा शाकाहारी है जो शायद नि:शुल्क देने पर भी इन उत्पादों का सेवन न करे।

दूसरी ओर ऐसे किफायती और पोषक वैकल्पिक उत्पादों की भी कोई कमी नहीं है जिन्हें पीडीएस के माध्यम से आसानी से वितरित किया जा सकता है। दालें और मोटे अनाज इसमें शामिल हैं। देश में व्यापक तौर पर उगाए जाने वाले फलीदार अनाजों को अगर गरीबों की आर्थिक पहुंच में लाया जा सके तो देश में प्रोटीन की कमी की समस्या दूर हो सकती है। उनका उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है ताकि पीडीएस के जरिये उसका वितरण हो सके। मांसाहारी उत्पादों की तुलना में दालों के वितरण में बहुत मामूली सब्सिडी देनी होगी। मोटे अनाजों को अब पोषक अनाज कहा जाने लगा है और अपनी पोषण क्षमता की बदौलत ये भी पीडीएस में जगह के दावेदार हैं। इनमें बाजरा, ज्वार, रागी आदि शामिल हैं जो उन सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से भरपूर हैं जो चावल और गेहूं में नहीं मिलते। चावल और गेहूं जैसे सब्सिडी वाले अनाज की उपलब्धता के पहले ये अन्न नियमित रूप से आम लोगों के भोजन का हिस्सा हुआ करते थे। कर्नाटक के एक स्कूल में जहां बच्चों को मोटा अनाज दिया जाता था, वहां हुए एक अध्ययन ने इन अनाजों के स्वास्थवर्धक गुणों को नए सिरे से सामने रखा है। हैदराबाद स्थित इंटरनैशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स और एक स्वयंसेवी संगठन अक्षय पात्र द्वारा कराया गया यह अध्ययन बताता है कि मध्याह्न भोजन में चावल की जगह मोटे अनाज को शामिल किया जाए तो बच्चों की वृद्धि में 50 फीसदी तक का सुधार हो सकता है।

मोटे अनाज के स्वास्थ्यवर्धक होने के नाते दुनिया भर में उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार भी उनके इस गुण से वाकिफ है। बल्कि उसने 2018 को मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया था। इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा किया गया ताकि उत्पादन बढ़ सके। परंतु पीडीएस के जरिये वितरण और उसके पहले सरकारी खरीद जैसी विपणन सहायता की उसे अभी भी प्रतीक्षा है। यदि नीति आयोग दालों और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने और इनकी सहायता से कुपोषण समाप्त करने का प्रयास करे तो बेहतर होगा बजाय कि पीडीएस के जरिये पशु उत्पादों के वितरण पर विचार करने के।

बिनय सिन्हा

अमेरिकी समाज में बढ़ती असमानता

अमेरिका में बढ़ती आर्थिक असमानता समाज के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं **पार्थसारथि शोम**

भारत और ब्राजील में बढ़ती असमानता के बारे में सभी जानते हैं। मैं काफी समय से इस बारे में लिखता भी रहा हूं। परंतु अमेरिका में बढ़ती असमानता शायद अधिक चौंकाने वाली बात है। द इकनॉमिस्ट पत्रिका का एक ताजा अंक इस चिंता को कम करके आंकने का प्रयास करता है। इसका शीर्षक है, 'असमानता के भ्रम: क्यों संपत्ति और आय का अंतर उतना नहीं है जितना वह नजर आता है।' इसने मुझे प्रतिक्रिया देने पर विवश किया है। इसमें हाल में आए विद्वतापूर्ण पर्चों के बारे में कहा गया कि उनके नतीजे पूर्व में उन पर्चों के परिणाम से विरोधाभासी हैं जिनमें कहा गया था कि अमेरिका में संपत्ति और आय के अंतर में तेजी से गिरावट आ रही है।

द इकनॉमिस्ट की कवरेज पर करीबी नजर डाली जाए तो पता चलता है कि नये पर्चों में पुराने पर्चों के नतीजों को उलटा नहीं गया है। बल्कि वे उन नतीजों की तीव्रता को कुछ हद तक कम करते हैं। ऐसे में यह निष्कर्ष अक्षुण्ण बना रहता है कि सन 1980 के दशक से अब तक असमानता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नये निष्कर्ष में नये आंकड़ों का अत्यंत चतुराईपूर्वक इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि पिछले निष्कर्षों को नकारने में उनकी अक्षमता दरअसल शुरुआती नतीजों की मजबूती की पुष्टि ही करती है। व्यापक आकलन की शुरुआत इस बात से की जानी चाहिए कि बाजार कैसे काम करते हैं? सन 1776 में आई एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस इसकी बुनियाद है। पुस्तक में कहा गया है कि वैयक्तिक लोग व्यक्तिगत लाभ से संचालित होते हैं। उनकी कारोबारी भावना बाजार में उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मूल्य पर अधिकतम वस्तुएं उपलब्ध कराती है। ऐसे में स्वार्थपरकता समाज कल्याण को बढ़ावा देती है। इसके पीछे पूरी तरह एक ही सिद्धांत है और वह है कि आपूर्तिकर्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा।

बाद में अर्थशास्त्रियों ने इस मॉडल में उस समय परिवर्तन किया जब कुछ आपूर्तिकर्ता रह जाते हैं जो बाजार की कीमतों को नियंत्रित कर सकते हैं तब बाजार की कीमतें प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगी और उपभोक्ताओं को ऊंची कीमत चुकानी होगी। चाहे जो भी हो लेकिन अदृश्य हाथ का सिद्धांत विश्वसनीय माना गया और बाजार के कामकाज के पीछे उसे ही मुख्य प्रेरणा माना गया।

इसके अलावा उत्पादन प्रक्रिया और श्रम उत्पादकता में सुधार के साथ तथा तकनीक के उन्नत होने के साथ आर्थिक वृद्धि दर में स्थिर वृद्धि आएगी। उस राह पर तमाम संसाधनों के मालिक यह अनुभव करेंगे कि उनकी पूंजी या उनके श्रम पर प्रतिफल भी उसी दर से बढ़ेगा। यदि यह वृद्धि आबादी में वृद्धि की दर के समान हो गई तो उससे अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी के बुनियादी नियम से ही समझौता हो जाता है।

वह नियम संसाधन मालिकों के शुरुआती दान के बारे में कुछ नहीं कहता। इसे सन 1896 में इटली के अर्थशास्त्री विफ्रेडो पारेटो ने स्थापित किया। एक उभरते और विद्रोही प्रकृति के अर्थशास्त्री के रूप में मैंने अपनी स्नातकोत्तर की थीसिस का विषय रखा, 'नॉन एथिकल डिस्ट्रिब्यूशन ऐंड फेल्योर्स ऑफ मार्केट।' इसे एक बार में स्वीकार कर लिए जाने पर मुझे खासी प्रसन्नता हुई थी।

सारा आर्थिक सिद्धांत परिपूर्ण बाजार की सक्षमता पर आधारित था। इसी तरह कराधान सिद्धांत आगे बढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आखिर विभिन्न करों का बोझ अंतत: किस पर जाता है। इसके नतीजे स्पष्ट थे और उनका सामान्यीकरण किया जा सकता था। उन्हें टैक्स इंसीडेंस थ्योरम कहा गया। बाजार के समक्ष अनुनय मुझे हमेशा परेशान करती थी। मेरी पीएचडी थीसिस ने दर्शाया कि कैसे किसी बाजार अर्थव्यवस्था में परिणामों की स्वच्छता आसानी से ध्वस्त हो सकती है।

मैं यहां अपने उक्त प्रयासों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया कि बाजार बिना किसी खामी के काम करते हैं। मैंने सन 1970 के दशक में जो निष्कर्ष और नतीजे दिए थे वे संक्षिप्त थे और अमेरिकी आर्थिक प्रतिष्ठान को यह यकीन नहीं दिला पाए कि बाजार में उसका भरोसा गलत था। शायद अपनी परिभाषा के दायरे में भी बाजार अर्थव्यवस्था ने सन 1970 तक व्यापक तौर पर स्वीकार्य प्रदर्शन किया, आर्थिक एजेंट्स को निवेश पर अच्छा प्रतिफल मिला और वेतन भत्तों में बढ़ोतरी हुई। लोगों के जीवन मानक में सुधार हुआ।

सन 1980 के दशक से बाजार प्रतिस्पर्धा के बुनियादी सिद्धांत में दरार आनी शुरू हो गई। नयी सहस्राब्दी में तो ऐसा और अधिक हुआ। सबसे पहले तो आर्थिक एजेंटों के बीच पूरी जानकारी विस्तारित थी और हर एजेंट को इतना छोटा रखा गया कि वह बाजार मूल्य को प्रभावित न कर सके। बाजार को अस्थिर करने की बात तो छोड़ ही दी जाए।

ये दोनों सिद्धांत धीरे-धीरे टूटने लगे। सूचना प्रौद्योगिकी की प्रचुरता के बीच सूचना जुटाना आसान हुआ। विश्लेषकों ने सुरक्षित वैश्विक आंकड़ों से सूचना जुटाना और वैश्विक जिंस कीमतों के अनुमान लगाना शुरू किया। जिन निवेशकों को जानकारी नहीं थी उन्होंने मामूली बढ़ोतरी पर अपने शेयर बेच दिए। जबकि सूचित निवेशकों ने कीमतें बढ़ने के बावजूद और अधिक खरीदारी की। इससे कीमतें और बाजार की बुनियाद अस्थिर हुई। जिनके पास सूचना थी उन्हें अपने निवेश की तुलना में कई गुना अधिक लाभ हासिल हुआ। वैश्विक बाजारों को अस्थिर करने और असंगत प्रतिफल हासिल करने के बाद वे वैश्विक परोपकारियों के रूप में सामने आए। यह नई सहस्राब्दी का विरोधाभास था। वित्तीय क्षेत्र समेत तमाम क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिला।

वृहद स्तर पर देखें तो बार-बार सामने आए वैश्विक संकटों में बाजार के औंधे मुंह गिरने के बावजूद ऐसे एजेंट अधिकतम मूल्य हासिल करने में कामयाब रहे। जबकि इसी अवधि में शेयर बाजार से खरबों डॉलर की राशि स्वाहा हो गई। इससे लाभान्वित होने वाले एजेंट वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े स्वरूप में उभरे। इसका असर छोटे प्रतिस्पर्धियों पर पड़ा। कुल मिलाकर इससे प्रतिस्पर्धी बाजार की छवि प्रभावित हुई। ऐसे में असमानता तो लाजिमी तौर पर आनी थी।

वृहद आर्थिक कारकों के अलावा नई सहस्राब्दी के वृहद आर्थिक संकेतक बताते हैं कि कैसे समूचे अमेरिका में आय में असमानता बढ़ रही है। यहां तक कि लिंग, नस्ल, आर्थिक गतिशीलता आदि सभी में असमानता बढ़ी है। हमने पत्रिका के जिस अंक से अपनी बात शुरू की, उसमें असमानता समाप्त करने को लेकर विचारों, विश्लेषण और नीतिगत कदमों में आमूलचूल बदलाव की बात निहित है। इसमें भारत के लिए भी अहम सबक हैं।

सरकार क्यों अपनाती हैं उथल-पुथल की राह?

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

मई 2014 और नवंबर 2016 के बीच मोदी सरकार पुराने ढर्रे पर चल रही थी और हर कोई यही शिकायत कर रहा था कि सरकार पर्याप्त तेजी से काम नहीं कर रही है। परंतु उसके बाद उसने जो तेजी अख्तियार की है वह कई बार बहुत अधिक उथल-पुथल करने वाली साबित हुई है।

बात चाहे नोटबंदी की हो या जीएसटी की या फिर तीन तलाक या अनुच्छेद 370 अथवा नागरिकता कानून में ताजा संशोधन की, सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने के बजाय इन्हें अचानक और बड़े पैमाने पर लागू करने का प्रयास किया है। यहां तक कि जेएनयू की शुल्क वृद्धि भी इस लिहाज से बहुत ज्यादा थी कि उसे 10 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2,400 रुपये प्रति माह किया गया।

इस व्यवहार को समझने के लिए शायद हमें वह समझना होगा जिसे जर्मन युगचेतना कहते हैं। इसके साथ ही उस कदम को भी देखना होगा जो सरकार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाले उठाते हैं। इसे अच्छी तरह समझने के लिए हमें सन 1969 के दौर में जाना होगा। उस वर्ष जुलाई में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी में विभाजन किया और वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सहायता से एक अल्पमत सरकार चला रही थीं। उसे प्रसन्न करने के लिए उन्होंने देश के 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर दी। यह वह व्यवस्था थी जिसके तहत गैर ब्रिटिश भारत के शासकों को मासिक तौर पर कुछ धनराशि दी जाती थी। यह राशि इसलिए दी जाती थी क्योंकि वे भारतीय गणराज्य में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा था कि वह विशेष अधिकार समाप्त कर रही हैं। सन 1971 से 1973 के बीच उन्होंने कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया।

उनके कोयला मंत्री पी कुमार मंगलम थे जो पहले वामपंथी रह चुके थे। सन 1973 में उन्होंने अनाज के कारोबार का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अच्छी बात यह थी कि यह कुछ ही महीने चला। सन 1974 से 1976 के बीच विदेशी तेल कंपनियों का भी निजीकरण कर दिया गया था। यह सब बहुत बड़ी उथलपुथल थी। इससे पहले देश ने ऐसा कुछ नहीं देखा था।

कारण

सरकार इतने बड़े पैमाने पर हंगामा क्यों खड़ा करती है इसे लेकर मेरे मन में दो व्याख्याएं हैं। इनमें से एक प्राथमिक है तो दूसरी नीतिगत। बाद वाली स्थिति के लिए सरकार को किसी ऐसे को प्रसन्न करना होता है जिसका समर्थन उसके अस्तित्व के लिए जरूरी हो। या फिर कोई ऐसा जो सत्ताधारी दल को वैचारिक संबल प्रदान कर सके।

परंतु इसे सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि पहली स्थिति बन चुकी हो। यानी युग चेतना आ चुकी हो। एक अच्छा राजनेता समझ जाता है कि यह कब हो रहा है और वह इसका फायदा उठाता है। इंदिरा गांधी ने सन 1960 के दशक के आखिर तक विकसित हुई संपत्ति के पुनर्वितरण की ललक को पहचान लिया था और उन्होंने इसका पूरा लाभ लिया। उस नजरिये से देखें तो यह समझना महत्त्वपूर्ण है कि व्यापक उथलपुथल की समस्या अकेले सरकार की खड़ी की हुई नहीं होती बल्कि इसके लिए देश का मिजाज भी वजह होता है जो बदलता है। ऐसे में वास्तविक प्रश्न यह होना चाहिए कि आखिर नया मिजाज क्यों आता है और राजनेता नया मिजाज बनाते हैं या वह मिजाज नेता बनाता है? उदाहरण के लिए सन 1960 के दशक के अंत तक न तो समाजवाद और न ही मौजूदा स्वरूप वाली धर्मनिरपेक्षता राजनीतिक मंचों पर नजर आती थी। इन बातों के बारे में कोई भी ज्यादा बात नहीं करता था। बल्कि इन विचारों को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाने को नापसंद किया जाता था और लोग इसे खारिज कर देते थे। जन संघ जैसे जिन दलों ने इस पर जोर दिया उनकी अनदेखी करनी उचित समझी गई। सन 1989 तक जन संघ का चुनावी प्रदर्शन इसका गवाह है। सवाल यह है कि बदला क्या? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था सन 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी की वामपंथ पर निर्भरता एक महत्त्वपूर्ण कारक थी। इसके चलते पुनर्वितरण का इस हद तक इस्तेमाल हुआ कि देश कुछ ज्यादा ही समाजवादी बन गया। सन 1976 में इंदिरा गांधी ने समाजवादी शब्द को देश के संविधान में भी जोड़ दिया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी उन्होंने ही इसका हिस्सा बनाया।

कारक

मुझे लगता है कि जिस तरह समाजवाद को लेकर मिजाज में बदलाव आया, वही स्थिति इन दिनों धर्मनिरपेक्षता के साथ बन चुकी है। इसके पीछे चाहे जो भी तात्कालिक या दीर्घकालिक कारण हों लेकिन सच यह है कि देश के लोग अब बहुत बड़ी तादाद में धर्मनिरपेक्षता से मुंह मोड़ चुके हैं। परंतु राजनीतिक लेनदेन की स्थिति हमेशा एकतरफा नहीं रहती। सन 1974 तक एक बड़े आर्थिक संकट और संसद और राज्य विधानसभाओं में भारी बहुमत के बल पर इंदिरा गांधी वामपंथ से दूरी बनाने में कामयाब रहीं क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद वह एक समाजवादी स्वरूप में ही सही लेकिन अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने और मजबूत बनाने में कामयाब रहीं।

इसकी तुलना वर्तमान से करते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को बमुश्किल सात महीने हुए हैं और इसने हर वह काम किया है जो पार्टी और उसका वैचारिक साझेदार चाहता है- तीन तलाक, अनुच्छेद 370 का खात्मा और नया नागरिकता अधिनियम।

परंतु अब जबकि बड़े राजनीतिक काम हो चुके हैं, समय आ गया है कि वह अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे जो असली समस्या बना हुआ है। संभाव्यता के सिद्धांत में इसे ऐसा बदलाव कहा जाता है जिसमें आप चर को इस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं कि चीजें आपके पक्ष में घटित हों। इंदिरा गांधी ने इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। अब मोदी भी ऐसा कर रहे हैं। हकीकत में उन्हें करना ही चाहिए। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण किया था, मोदी को इसे समाप्त करना चाहिए।

कानाफूसी

चॉकलेट वाले पुलिसकर्मी

देश भर में क्रिसमस, नए साल के आगमन के साथ-साथ अन्य त्योहारी मौसम की धूम है और त्योहारों का रंग गोवा की पुलिस पर भी चढ़ गया है। गोवा पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के बजाय उन्हें चॉकलेट भेंट की। इतना ही नहीं पणजी में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों ने क्रिसमस के मौके को देखते हुए सांता क्लॉज की पोशाक भी पहनी। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को यातायात सुरक्षा और संबंधित नियमों को लेकर लंबा-चौड़ा भाषण भी सुनना पड़ा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ लोगों को यह सब मजेदार लगा क्योंकि उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ा। वहीं अन्य लोग इस बात को लेकर संशय में थे कि यह कवायद जरूरी संदेश दे भी पाएगी या नहीं।

दारू नहीं सिर्फ दवा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को शहर की झुग्गियों और झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए 'मुख्यमंत्री आवास योजना' की शुरुआत की। ध्यान रहे कि दिल्ली में फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस अवसर पर केजरीवाल ने कहा कि पिछले पांच साल में उनकी सरकार ने आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा, 'आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया।' इसके बाद थोड़ा रुकने के बाद उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने केवल 'दवा' का इंतजाम किया है 'दारू' का नहीं। इसके बाद हंसी के फव्वारों के बीच उन्होंने भीड़ में पीछे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि 'देखो, वह आदमी खुश हो गया वहां।'

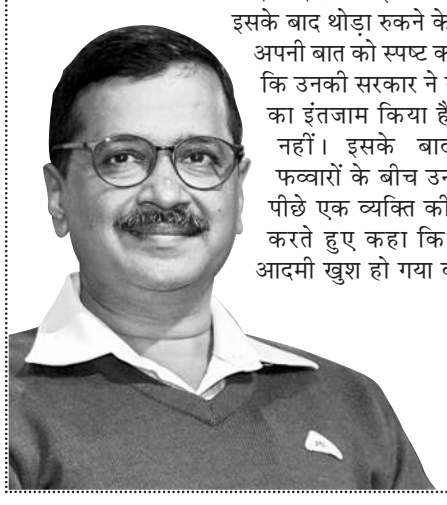

आपका पक्ष

गरीबों की योजनाओं पर अमीरों का ग्रहण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के हर गरीब की रसोई तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की है। सरकार ने उन गरीब परिवारों तक मुफ्त रसोई गैस देने के लिए पहल की है जो 21वीं सदी में भी कोयले या लकड़ी जलाकर रसोई चलाते थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के तहत उन गरीब परिवारों तक रसोई गैस पहुंचाने के लिए प्रयास किए जो किन्हीं कारणों से उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पाए। लेकिन देश के कुछ समृद्ध लोग भी सरकार की मुफ्त की सुविधाओं को लेना चाहते हैं। इसका उदाहरण हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के लिए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन लेने वालों में कुछ फर्जी आवेदनों का आना है। अगर केंद्र और राज्य सरकार मुफ्त की दी जा रही सेवाओं की निष्पक्ष और उचित जांच करे तो बहुत चकित करने वाले आंकड़े सामने आएंगे। अक्सर

देखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाती हैं वे भ्रष्टाचार के कारण दूर दूराज गांवों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं और जरूरतमंद लोग सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। सरकारों को इन योजनाओं को अमल में लाने के साथ ऐसी व्यवस्था का इंतजाम करना चाहिए कि कोई भी अपने चहेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे पाए और किसी अमीर व्यक्ति को गरीबों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सके।

गरीबों के लिए बनी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन उचित तरीके से होना चाहिए

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

सहकारी बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस

सहकारी बैंकों में कॉरपोरेट गवर्नेंस लाने से इनकी हालत सुधारने में मदद मिल सकती है। इन बैंकों में ऑडिटर को और अधिक जवाबदेह बनाना होगा जिससे घोटालों को रोका जा सके। सहकारी बैंकों की मौजूदा खस्ताहालत को देखते हुए रिजर्व बैंक को अधिक शक्तियां देने का समय आ गया है जिससे सही निर्णय लिया जा सके। सहकारी बैंकों से ग्राहकों के उठ चुके भरोसे को बहाल करने के लिए भी कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए सहकारी बैंकों में घोटाला होने पर जमाकर्ताओं की राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के नियम बनने चाहिए। जिसके तहत उनकी जमा राशि निकालने पर पाबंदी न लगाने का नियम हो।

नीतू वर्मा, झांसी

भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने की जरूरत

देश में भिक्षावृत्ति सड़क किनारे, धार्मिक स्थल या चौक-चौराहों पर दिख जाती है। भारत में भीख मांगना और भीख देना पौराणिक कर्म है। इसे दान की श्रेणी में रखा जाता है। इस वजह से यहां भिक्षुकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। देश में एक वर्ग ऐसा है जिनके पास भोजन, कपड़ा और आवास नहीं हैं। यह वर्ग मजबूर होकर भिक्षावृत्ति अपना लेता है। लेकिन आज भिक्षावृत्ति ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है जो दया, सहानुभूति जैसी मानवीय भावनाओं का लाभ उठाते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए वास्तविक स्थिति का पता सर्वेक्षण के जरिये लगाया जा सकता है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कानून बनाने की जरूरत है। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के शिकार लोगों तक मौलिक सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत है। भिक्षावृत्ति से जुड़े लोगों के लिए पुनर्वास योजना बनाने की जरूरत है।

अनु मिश्रा, सीवान

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

सलाखों से बाहर भी अधूरी रिहाई...

कैदी जब जेल से रिहा होते हैं तो उनके सामने चुनौतियों की और भी ऊंची दीवारें खड़ी होती हैं - सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की दीवारें

वीरेश्वर तोमर

पंजाब के जालंधर में रहने वाले विक्रम दो दिनों से एक ढाबे पर वेटर का काम कर रहे थे। आज उन्हें एक कार्यक्रम में शामियाना लगाने जाना है। विक्रम दिहाड़ी मजदूर हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि वह पढ़े-लिखे नहीं हैं। विक्रम के पास बीए की डिग्री के साथ ही मानवाधिकार तथा पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम करने का अनुभव भी है। इतना ही नहीं, वह सिलाई के हुनर में भी माहिर हैं। लेकिन इतनी योग्यता के बाद भी उनके पास ढंग की नौकरी नहीं है क्योंकि 10 साल का वह अरसा उनके और नौकरी के बीच आड़े आ जाता है, जो उन्होंने गाजियाबाद की डासना जेल में बिताया था।

विक्रम को 2006 में गाजियाबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह अपनी मां के साथ गाजियाबाद में रहते थे। विक्रम बताते हैं, 'मेरे पिता नशा करते थे और घर आकर मारपीट करते थे। कुछ समय बाद वह हमसे अलग रहने लगे, लेकिन उनके काम-धंधे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे किसी भी तरह खुद को और मां को पालना था और उस वक्त मुझे वही रास्ता नजर आया।'

विक्रम को अदालत ने दोषी पाया और 10 साल के लिए जेल भेज दिया। विक्रम कहते हैं, 'जेल में पहली रात मुझे आज तक याद है। मैं एक मिनट भी नहीं सो पाया। मां का चेहरा याद आता था और चिंता हो रही थी कि उनके खाने-पीने का इंतजाम कौन करेगा। जेल में हर तरह के लोग आपके इर्द-गिर्द होते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाई का रास्ता अपनाया।' विक्रम ने जेल में रहते हुए ही 10वीं, 12वीं और बीए की पढ़ाई पूरी की। वहां उन्होंने सिलाई और नृत्य सीखा तथा मानवाधिकार और पर्यावरण का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया।

सजा काटकर विक्रम 5 अगस्त 2017 को बाहर आ गए, लेकिन समाज ने अब तक उन्हें स्वीकार नहीं किया है। पहले उन्होंने घर बदला फिर नौकरियां तलाशीं। पहले एटीएम में गार्ड की नौकरी की, उसके बाद पंजाब के एक नामी अस्पताल में वार्ड बॉय बन गए। लेकिन पढ़ाई के दस्तावेजों में लिखा जेल का पता एक बार फिर आड़े आ गया और दो दिन बाद ही उन्हें अस्पताल से निकाल दिया गया।

यह कहानी केवल विक्रम की नहीं है। जेल सुधार के लिए काम करने वाली संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन की निदेशक मोनिका धवन बताती हैं कि हमारे चारों ओर ऐसे कई लोग हैं, जो किसी वजह से जेल जाने के बाद बेहतर बनकर लौटे, लेकिन समाज ने कभी उन्हें माफ नहीं किया। वह कहती हैं, 'समाज उन्हें स्वीकारने से कतराता है और उनसे दूरी बना लेता है। कई साल जेल में बिताने के बाद जब वे एकदम बदली हुई दुनिया में दाखिल होते हैं और उनके पास नौकरी के सीमित विकल्प होते हैं तो समाज उन्हें एक बार फिर उसी दुनिया में लौटने के लिए मजबूर क्यों करता है।'

आवाज में भारीपन और मायूसी के साथ विक्रम बताते हैं, 'मेरी मां ने मुझे आज तक माफ नहीं किया। मेरे जेल में रहते हुए एक बार उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे बीमार रहने लगीं। अब वह वृद्धाश्रम में हैं और मुझसे नाराज हैं।' विडंबना ही है कि बड़ी तादाद में ऐसे कैदी भी हैं, जिनका मामला विचाराधीन है यानी जिनका अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है और जिनके मामलों की सुनवाई चल रही है। लेकिन अदालत में मुकदमों के अंबार के कारण कई बार सुनवाई महीनों या वर्षों तक चलती रहती है और वह अरसा उन्हें जेल में गुजारना पड़ता है। टाटा ट्रस्ट द्वारा नवंबर 2019 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक देश की जेलों में करीब 68 फीसदी कैदी विचाराधीन हैं। दिक्कत यह है कि निर्दोष सिद्ध होने के बाद भी जेल से बाहर आने पर उन्हें आम कैदियों या अपराधियों की ही तरह समाज का तिरस्कार झेलना पड़ता है, जो उन्हें सामान्य जीवन बिताने से रोकता है।

नई चुनौतियां

करीब साढ़े तीन साल जेल में रहने के बाद 2015 में गाजियाबाद जेल से बाहर आए प्रीतेश सिंह रघुवंशी का कहना है कि जेल जाने से उनका पूरा परिवार कई साल पीछे चला गया। वह कहते हैं, 'मेरे जेल जाने की खबर के बाद बहन की ससुराल वाले उसे परेशान करने लगे और कुछ समय बाद उसे घर से निकाल दिया। मां-पिता बीमार रहते थे मगर उनकी दवा के इंतजाम का कोई साधन मेरे पास नहीं था।'

> जेल सुधार पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि रिहाई के बाद कैदियों को तिरस्कार, मानसिक तनाव तथा अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे में वे नई शुरुआत कैसे करें?

प्रीतेश आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के पास बिनुपुर गांव के रहने वाले हैं। वह मारुति सुजुकी के मानेसर संयंत्र में क्वालिटी मैनेजमेंट इंचार्ज के पद पर काम करते थे। 2012 में उस संयंत्र में हुई बहुचर्चित हिंसा में उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने उसी साल 19 जुलाई को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन से उनकी जिंदगी का स्याह पन्ना शुरू हो गया। अदालत ने आखिरकार प्रीतेश को बेकसूर करार दिया मगर बाहर नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। वह कहते हैं, 'जेल से बाहर आने पर आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, अपराध की दुनिया का और दूसरा, समाज में बेहतर तथा नई जिंदगी का। पहला तरीका आसान है क्योंकि आप जेल से आ रहे हैं, जहां आपको हर तरह के लोग मिले थे। दूसरे तरीके के लिए न तो समाज आपका साथ देता है और न ही नई शुरुआत के लिए आपके पास पैसा या जगह होती है।'

ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क से जुड़ीं जेल सुधार कार्यकर्ता सिस्टर सुमा कैदियों का दर्द बयां करती हैं, 'जेल से बाहर आने के बाद कोई उनसे मिलना नहीं चाहता, नौकरी नहीं देना चाहता। समाज बहुत जल्दी बदल रहा है और बाहर आने पर उन्हें एकदम नई दुनिया मिलती है। ज्यादातर कैदियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और रिहाई के बाद उन्हें मानसिक तनाव, तिरस्कार तथा अपमान झेलना पड़ता है। ऐसे में वे नई शुरुआत कैसे करें?'

ऐसा भी नहीं है कि सजा काटने के बाद व्यक्ति पूरी तरह चौराहे पर खड़ा होता है। कुछ संस्थाएं और सरकार की नीतियां उसकी मदद करती हैं। मसलन दिल्ली में कैदियों को पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक मदद दी जाती है। 6 महीने से 5 साल तक सजा काटने वाले को 30,000 रुपये, 5 से 10 साल की सजा वाले को 40,000 रुपये और 10 साल से अधिक सजा काटने वाले व्यक्ति को 50,000 रुपये बाहर निकलने पर दिए जाते हैं। मगर ज्यादातर राज्यों में ऐसी कोई नीति नहीं है और दिल्ली जैसे शहर में आजकल यह रकम बहुत मामूली होती है। इसलिए जेल से बाहर आते ही सामाजिक तिरस्कार से भी बड़ी चुनौती आर्थिक भरण-पोषण की होती है। सजा काटकर निकलने वाले व्यक्ति को अगर सामाजिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर दिक्कतें आएं तो वह गलत राह भी चुन सकता है। दिल्ली में साकेत इलाके के गोविंद को चोरी, लूटपाट और हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। 2004 में उन्हें साथियों के साथ फरीदाबाद जेल भेज दिया गया। गोविंद 2006 में जमानत पर बाहर आए, लेकिन कुछ अरसा बाद उन्हें दोषी पाते हुए दोबारा जेल भेज दिया गया। सजा पूरी करने के बाद जनवरी 2016 में जेल से बाहर आए गोविंद के माता-पिता ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। वह कहते हैं, 'उन्होंने अपना फर्ज जरूर निभाया। शुरू में वे मुझसे मिलने जेल आते थे। बाद में काफी अरसे तक कोई नहीं आया तो पता चला कि मां को लकवा मार गया और पिता 2015 में चल बसे।'

गोविंद की कहानी सुनकर लगता है कि जेल से बाहर आए व्यक्ति के लिए गलत राह चुनना सबसे आसान विकल्प होता है। वह बताते हैं, 'जेल में रहते हुए मैं कई गिरोहों के संपर्क में आया। वे हमारी काफी मदद करते थे और हम भी उनकी ओर झुकते चले गए। 2006 में जमानत पर बाहर निकलने के बाद कुछ दिन मैंने उनके लिए काम भी किया।' मगर 2016 में जब गोविंद बाहर आए तो दिल्ली बदल चुकी थी, उनका घर बदल चुका था। हफ्तों बाद उन्हें पता चल पाया कि छोटा भाई कहां रहता है।

जालंधर निवासी विक्रम से जब पूछा गया कि उनका अतीत पता चल जाए तो पड़ोसी क्या करेंगे तब उन्होंने कहा, 'सब बदल जाएंगे। अभी सब अपने घरों में आने देते हैं। खुलासा हो गया तो शक की निगाहों से देखने लगेंगे। कई राज हमें छिपाने ही पड़ते हैं।'

महिलाओं की ज्यादा चुनौती

किसी भी सजायाफ्ता या जेल में रह चुके शख्स के लिए बाहर सामान्य जिंदगी जीना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वह महिला हो तो चुनौतियां और भी बड़ी हो जाती हैं। जालसाजी और लूटपाट के आरोप में 2 साल तक जेल में रहीं रेखा (बदला हुआ नाम) को इसका अहसास अच्छी तरह हो रहा है। वह बताती हैं, 'मेरी 4 साल की बच्ची है। जब मेरे पति को मेरे जेल जाने की खबर मिली तो उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया। साथ ही बेटी को भी उसने बेसहारा छोड़ दिया। मेरी बहन ने किसी तरह मेरी बच्ची को पाला। जेल से बाहर आते ही मैंने अपना ठिकाना बदल लिया है और अब दिहाड़ी मजदूरी कर मैं बसर कर रही हूं।'

रेखा को यह नहीं पता कि महिला कैदी के 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जेल में विशेष पालन गृह (क्रेच) होते हैं। रेखा ही नहीं कई महिला कैदियों को क्रेच के बारे में नहीं पता होता और उन्हें अपने नन्हे बच्चे बाहर छोड़ने पड़ते हैं। हालांकि जेल में इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होती है। तिहाड़ जेल ने सूचना के अधिकार के तहत पूछे एक सवाल के जवाब में बताया कि 22 नवंबर 2019 को केंद्रीय कारागार संख्या 16 (जो विशेष तौर पर महिला कैदियों के लिए बनाई गई है) में कुल 258 महिला कैदी थीं। यह भी बताया गया कि इन महिला कैदियों के साथ 6 वर्ष तक की उम्र के कुल 22 बच्चे वहां बने क्रेच में रह रहे थे। क्रेच में बच्चों की सभी सहूलियतों का खयाल रखा जाता है। उन्हें शिक्षा, भोजन, कपड़े और जरूरत का सामान मुहैया कराया जाता है।

चित्रांकन: अजय मोहंती

प्रीतेश अब जेल सुधार के लिए काम करने वाली संस्था इंडिया विजन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं (ऊपर) वहीं जेल में रहकर 10वीं, 12वीं, बीए के अलावा दूसरे सर्टिफिकेट कोर्स कर चुके विक्रम को अभी भी नौकरी खोजने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है (नीचे)

जेलों की स्थिति

- भारतीय जेलों में क्षमता के मुकाबले 114 फीसदी कैदी, इनमें से 67.7 प्रतिशत विचाराधीन, एक दशक पहले 66 प्रतिशत कैदी थे विचाराधीन
- अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 2.8 करोड़ मामले विचाराधीन, इनमें से 28 प्रतिशत मामलों पर 5 वर्षों से अधिक समय से चल रही सुनवाई
- 23 लाख मामले 10 साल से अधिक समय से विचाराधीन
- बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, मेघालय में प्रत्येक चार में से एक मामले पर पांच वर्षों से अधिक समय से हो रही सुनवाई
- जेल अधिकारियों के 20 प्रतिशत से अधिक पद खाली
- उत्तर प्रदेश में 95,000 कैदियों के लिए केवल एक करेक्शनल स्टाफ स्वीकृत
- लंबे समय तक सुनवाई के चलते कैदी समाज में आ रहे बदलावों से रह जाते हैं अनभिज्ञ
- उत्तर प्रदेश में जेल क्षमता से अधिक 37,000 कैदी
- देश की कुल 1,412 जेलों के लिए केवल 621 करेक्शनल स्टाफ मौजूद
- 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 लोगों पर मात्र एक न्यायाधीश
- जेल संबंधी रैंकिंग में केरल पहले स्थान पर, महाराष्ट्र और कर्नाटक दूसरे तथा तीसरे स्थान पर
- 16 राज्यों तथा यूटी में कैदियों के भोजन, कपड़े, चिकित्सा आदि पर 2,500 रुपये महीने से भी कम राशि होती है खर्च

स्रोत:टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019

जेल में ही सुधार और कैदियों के भविष्य पर ध्यान देने की जरूरत

आम मान्यता यही है कि अपराधियों या भटके हुए लोगों को सही राह पर लाने या उनका सुधार करने के लिए उन्हें जेल में भेजा जाता है। लेकिन हकीकत में जेलों के भीतर कैदियों को सुधारने की ठोस व्यवस्था है ही नहीं। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि जेल से बाहर आने के बाद कैदियों के पुनर्वास यानी उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की फिक्र सरकारों के भीतर नहीं दिखती। चुनिंदा गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) या इक्का-दुक्का राज्यों में जेल प्रशासन इसकी चिंता कर लेता है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे नजरअंदाज ही किया जाता है, जिसका खमियाजा सजा काटकर बाहर आने वालों को भुगतना पड़ता है।

दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों में पिछले 25 वर्षों से जेल सुधार पर काम कर रही इंडिया विजन फाउंडेशन की निदेशक मोनिका धवन बताती हैं कि कैदियों के पुनर्वास के लिए सरकारी नीतियां दिखती ही नहीं हैं। वह कहती हैं कि जेल राज्य का विषय है, लेकिन कुछेक राज्यों के अलावा कहीं भी कैदियों के पुनर्वास के नियम ही नहीं हैं। इस बारे में सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब में पता चला कि दिल्ली में कैदियों के पुनर्वास की नीति है, जिसके अंतर्गत सजा काटकर बाहर निकले कैदियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें 6 महीने से 5 साल तक सजा काटने वाले व्यक्ति को 30,000 रुपये, 5 से 10 साल की सजा वाले व्यक्ति को 40,000 रुपये और 10 साल से अधिक की सजा काटकर बाहर आए व्यक्ति को 50,000 रुपये बतौर आर्थिक सहायता प्रदान किए जाते हैं। लेकिन अक्सर कैदियों को इसकी जानकारी ही नहीं होती क्योंकि उन्हें जेल से बाहर आने की जल्दी होती है।

गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में विभिन्न राज्यों में कुल 722 एनजीओ जेल सुधार से जुड़े थे। इनमें सबसे ज्यादा 143 उत्तर प्रदेश में थे। मगर रिपोर्ट पर बारीक नजर डालने से पता चलता है कि इनमें केवल 23 एनजीओ कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहे थे। बाकी सब जेल के भीतर आध्यात्मिक चिंतन, योग, प्राणायाम और कौशल विकास में मदद कर रहे थे।

इंडिया विजन फाउंडेशन द्वारा जारी 2019 की सालाना रिपोर्ट में बताया कि संस्थान ने इस वर्ष कुल 13,926 कैदियों को कौशल विकास एवं पुनर्वास में मदद की है और इनमें से 429 जेल से बाहर आने के बाद भी उनसे संपर्क में हैं। मगर हकीकत में इससे कई गुना प्रयास की जरूरत है क्योंकि कैदियों की बड़ी तादाद इससे अछूती रह जाती है।

टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जेलों में क्षमता से 14 फीसदी अधिक कैदी हैं, जिनमें करीब 68 फीसदी विचाराधीन कैदी हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश की अदालतों में करीब 2.8 करोड़ मामले विचाराधीन हैं और उनमें से 28 फीसदी 5 साल से भी ज्यादा अरसे से लटके हुए हैं। अगर इन्हें समुचित कौशल देकर पुनर्वास के लायक नहीं बनाया जाता है तो मुख्यधारा में जुड़ने के बजाय ये गलत राह पर जा सकते हैं।

जेल सुधार कार्यकर्ता सिस्टर सुमा कहती हैं कि कैदियों को शिक्षित करके उन्हें सही राह पर लाया जा सकता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों में से 28.2 प्रतिशत अशिक्षित और 42.2 प्रतिशत कक्षा 10 से कम (कुल 70.08 प्रतिशत) पढ़े लिखे थे। यदि इन्हें पढ़ाने के साथ ही सिलाई, कंप्यूटर, नृत्य, पेंटिंग और छोटे-मोटे हुनर का प्रशिक्षण दिया जाता है तो उन्हें नया जीवन शुरू करने में काफी मदद मिलेगी।

पुराने चावल से जैव ईंधन बनाने की तैयारी

जिन चावलों का कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता, उन्हें ही बायो डीजल के लिए उपयोग में लाया जाएगा

संजीव मुखर्जी और शाइन जैकब
नई दिल्ली, 25 दिसंबर

केंद्र सरकार खाद्यान्न आधारित जैव ईंधन इकाइयों के फीडस्टॉक के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को लगभग 15 लाख टन टूटे हुए चावल के निपटान का आदेश दे सकता है। इस कदम से सूखे तथा भारी बारिश के चलते गन्ना उत्पादन में आई कमी की भरपाई हो सकेगी और यह देश की 'तेल के लिए खाद्य' नीति के लिए अहम पड़ाव साबित होगा। सूत्रों का कहना है कि इस कदम का दोहरा प्रभाव होगा।

पहला, इस कदम से फीडस्टॉक की कमी के कारण 75 करोड़ लीटर अनाज आधारित डिस्टिलरी क्षमता की गिरावट में कमी आएगी। दूसरा, इससे एफसीआई के पास रखे अधिशेष चावल का उपयोग होगा। अनुमानों के मुताबिक, एफसीआई के पास दिसंबर 2019 में 2.12 करोड़ टन चावल है जो वर्तमान में जरूरत का तीन गुना है।

देश में अनाज आधारित डिस्टिलरी की कुल क्षमता करीब 2 अरब लीटर है जिसके करीब 38 प्रतिशत (75 करोड़ लीटर) हिस्से का फीडस्टॉक की अनुप्लब्धता के चलते उपयोग नहीं हो पाता।

अधिकारियों का कहना है कि निपटान की इस प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल टूटे हुए चावल (वर्तमान रूप में मानव उपभोग के लिए पूरी तरह से अयोग्य) ही बायो डीजल के लिए उपयोग में लाए जाएं।

यह ऐसी किसी भी गलतफहमी को दूर करेगा कि जब देश के लाखों बच्चे कुपोषित हैं तो खाद्य भंडार को ईंधन के लिए बरबाद क्यों किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है बहुत जल्द इस संबंध में एक औपचारिक निविदा तथा संबंधित नीति की घोषणा होने की उम्मीद थी। जरूरत पड़ने पर इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनाज आधारित बायोडीजल इकाइयों को उचित कीमतों पर टूटे हुए चावल मिलें, 22-23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर सहमति बनने की संभावना है। यह कीमत इस अनुपयुक्त चावल के भंडार में होने वाले अनुमानित खर्च (27 रुपये प्रति किलो) से कम है।

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) टूटे हुए चावल से बने एथनॉल को 59.48 रुपये लीटर पर खरीदने के लिए सहमत हुई हैं। यह मानव उपभोग से बेकार अनाज से बनाए जा रहे एथनॉल की निर्धारित वर्तमान दर से अधिक है ताकि अनाज आधारित डिस्टिलरी इकाइयों को निवेश पर कुछ लाभ मिल सके। वर्तमान में यह कीमत 47.63 रुपये प्रति लीटर है। नई कीमत पर चर्चा होनी शुरू हो गई है क्योंकि अनाज आधारित डिस्टिलरी इकाइयों का कहना है कि अगर चावल के दाम कम रहते हैं तो 47.63 रुपये की कीमत भी ठीक है। लेकिन अब जब खुले बाजार और एफसीआई द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के तहत बेचे जाने वाले चावलों की कीमतें बढ़ गई हैं तो वर्तमान कीमत लाभदायक नहीं रह गई हैं। 75 करोड़ लीटर क्षमता वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी इकाइयों की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होने के पीछे यह एक बड़ा कारण है।

डिस्टिलरी इकाइयां चाहती हैं कि एफसीआई गोदामों से आने वाले टूटे हुए चावल की कीमत 22-23 रुपये किलो हो जबकि ओएमसी इस अनाज से उत्पादित एथनॉल को वर्तमान मूल्य से अधिक दर पर खरीदती हैं।

अधिकारियों का कहना है कि सरकार दोनों सुझावों पर गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि वह जल्द से जल्द 10 प्रतिशत एथनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को शुरू करना चाहती है, और इस लक्ष्य को केवल गन्ने की मदद से पूरा नहीं किया जा सकता। इस साल 5.11 अरब लीटर एथनॉल की आवश्यकता के मुकाबले चीनी मिलों तथा अनाज-आधारित डिस्टिलरी इकाइयों ने मिलकर 2019-20 (दिसंबर-नवंबर) में केवल 1.6 अरब लीटर एथनॉल के लिए बोलियां लग इसने वर्ष 2020 तक 10 प्रतिशत एथनॉल सम्मिश्रण योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना में दूसरी समस्या ऐसे वेयरहाउसों का चुनाव करना है जहां एफसीआई के पास अधिशेष अनाज है और अनाज आधारित डिस्टिलरी इकाइयां भी आसपास ही स्थित हों, जिससे परिवहन लागत को कम रखा जा सके।

इसके लिए केंद्र ने राज्यों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है और अधिशेष उत्पादन करने वाले क्षेत्रों की पहचान कर पास स्थित डिस्टिलरी इकाइयों का पता लगा रही है। छत्तीसगढ़ ने इस प्रस्ताव पर काम करना भी शुरू कर दिया है। भूपेश बघेल सरकार ने अक्टूबर महीने में एक निविदा जारी की जिसमें अनुमान लगाया गया है कि राज्य की पीडीएस संबंधी जरूरतों के बाद छत्तीसगढ़ में करीब 38 लाख टन चावल अधिशेष मात्रा में है। इसका उपयोग अनाज आधारित एथनॉल उत्पादन में किया जा सकता है। यह निविदाराज्य में नई जैव-रिफाइनरियों की स्थापना के लिए है।

बघेल ने नवंबर में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कहा था कि वे उन राज्यों को इसकी अनुमति दें जिनके पास जैवईंधन बनाने के लिए चावल अधिशेष है। अनाज आधारित एथनॉल संयंत्रों के लिए फीडस्टॉक में किसी भी भविष्य की कम की आशंका पर अधिकारियों ने बताया कि उ अनुमान के हिसाब से देश में उत्पादित ल 14 प्रतिशत अनाज (चावल तथा गेहूं) रह जाता है। दो वर्ष बाद यह अधिशे जाएगा और उस समय की स्थिति नहीं बचेगा। इस बीच, पेट्रोलि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रो वे गन्ने के अलावा दूस दूसरी पीढ़ी की 12 लगाएं। एक अधि तक इस तरह के देंगे।' दूसरी विनिर्माण बहु-मॉ किया गेहं

अनाज से तेल

- **5.11 अरब लीटरः वित्त वर्ष 2019-20 में तेल विपणन कंपनियों के लिए एथनॉल की आवश्यकता**
- **1.66 अरब लीटर : फिलहाल आपूर्ति के लिए उपलब्ध एथनॉल**
- **2 अरब लीटरः अनाज आधारित एथनॉल इकाइयों की क्षमता**
- **75 करोड़ लीटरः फीडस्टॉक की कमी के कारण अनुपयोगी क्षमता**
- **2.12 करोड़ टनः एफसीआई के गोदामों में चावल की मात्रा (11 दिसंबर)**
- **76.10 लाख टनः प्रत्येक वर्ष जनवरी के समय केंद्रीय भंडार में चावल की आवश्यकता**

उड़द के दाम दो मही में बढ़े 20 प्रतिशत

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 25 दिसंबर

- **अन्य द सरक**
- **स**

उड़द के भाव पिछले दो महीने के दौरान 20 फीसदी बढ़े हैं। दरअसल मॉनसून सीजन में भारी बारिश और बाढ़ से खरीफ सत्र की उड़द की फसल को नुकसा पहुंचा था। सरकार के स्वामित्व ए एगमार्कनेट पोर्टल के आंकड़ों से चलता है कि बेंचमार्क महाराष्ट्र मंडी में उड़द के भाव बढ़क प्रति किलोग्राम पर पहुंच ग अक्टूबर की शुरुआत में प्रति किलोग्राम थीं।

उड़द का यह मूल्य (एमएसपी उड़द की दाल प्रति किलोग्रा होने से अ सभी दा मध्य

सस्ते आयात की मार

प्लास्टिक उद्योग को शुल्क वृद्धि की दरकार

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 25 दिसंबर

निर्यात में तेज गिरावट और आयात में इजाफे का सामना कर रहे देश के प्लास्टिक विनिर्माताओं ने विदेशों से सस्ते और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति रोकने के लिए सरकार से सीमा शुल्क बढ़ाने, डंपिंग रोधी शुल्क लगाने और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा करने का अनुरोध किया है।

देश के प्लास्टिक उद्योग में फिर से जान फूंकने के लिए जरूरी उपायों पर विचार-विमर्श करने की खातिर प्लास्टिक विनिर्माताओं ने अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता संघ (एआईपीएमए) के तत्वावधान में इस मूल्य श्रृंखला के अन्य भागीदारों के साथ बैठक की है। एआईपीएमए प्लास्टिक और संबंधित उत्पादों की तकरीबन 22,000 औद्योगिक इकाइयों का नेतृत्व करता है। बैठक में इन विनिर्माण इकाइयों को बंद होने से बचाने और प्लास्टिक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग को रफ्तार की राह पर लाने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया है। एआईपीएमए की संचालन परिषद के चेयरमैन अरविंद मेहता ने कहा कि वर्तमान में प्लास्टिक उद्योग को बाजार में दबाव नजर आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों ने अपने विस्तार और निवेश की योजनाओं को रोक दिया है। रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विभिन्न मोर्चों पर स्पष्ट योजनाएं और रणनीति के साथ सामने आने की जरूरत है। अक्टूबर 2019 में देश ने 69.3 करोड़ डॉलर मूल्य का प्लास्टिक निर्यात किया था जो पिछले साल इसी महीने में दर्ज 77.8 करोड़ डॉलर की तुलना में 10.9 प्रतिशत कम है। अप्रैल से अक्टूबर 2019 के दौरान प्लास्टिक निर्यात का कुल मूल्य 5.02 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 5.37 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात दर्ज किया गया था। एआईपीएमए के अध्यक्ष जगत किलावला मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में प्लास्टिक उद्योग प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है और पांच लाख करोड़ डॉलर की बनने जा रही भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। मांगों के संबंध में किलावला ने कहा कि प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयों के लघु अवधि के साथ-साथ दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग ने सरकार से प्रमुख कच्चे माल पर नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों पर निश्चित रूप से आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है।

करीब 50 लाख कर्मचारियों को रोजगार देने वाले इस प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में 50,000 से ज्यादा सूक्ष्य और लघु इकाइयां शामिल हैं। सालाना 3.75 लाख करोड़ रुपये मूल्य वाली वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका प्रमुख योगदान रहता है। हालांकि यह चीन और अन्य दक्षिण एशियाई देशों से सस्ते आयात के कारण काफी दबाव में है। उद्योग ने मांग की है कि कच्चे माल और प्लास्टिक से तैयार उत्पाद के बीच सीमा शुल्क का न्यूनतम अंतर 10 प्रतिशत बनाए रखा जाना चाहिए। चीन और अन्य देशों द्वारा सस्ते उत्पादों की डंपिंग की वजह से घरेलू उद्योग परेशानी झेल रहा है। उद्योग ने विदेशी कंपनियों को सस्ता माल बेचे जाने से रोकने के लिए तैयार माल की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने की भी मांग की है। एक विशेषज्ञ ने कहा व्यापार महानिदेशालय को कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए डंपिंग करने वाले चीन सहित तीन देशों में बनने वाले या वहां से आयातित प्लास्टिक के तैयार उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए। विभिन्न देशों के साथ किए गए मौजूदा एफटीए वांछित परिणाम देने में असफल रहे हैं। इससे भारत में इन देशों से शून्य या रियायती शुल्क पर तैयार माल का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है जिससे भारतीय प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की प्रतिस्पर्धा बुरी तरह प्रभावित हुई है।

अर्थव्यवस्था

आकार सिकुड़ने की आहट

6 फरवरी

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने खुलासा किया था कि सरकार ने एनएसएसओ का एक सर्वेक्षण दबा रखा है, जिसके मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी चार दशक के सर्वोच्च स्तर पर थी। मोदी सरकार ने पहले नतीजे सर्वेक्षण के नतीजों को को पुरजोर खारिज किया और फिर इसे चुनावों के बाद जारी किया।

1 फरवरी

अरुण जेटली के बीमार होने की वजह से पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया। इसमें पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट और किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद की घोषणा की गई।

4 जुलाई

भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इसमें दो करोड़ रुपये से अधिक आमदनी वाले लोगों पर आयकर अधिभार लागू किया गया।

धीमी और अस्थिर

जीडीपी वृद्धि दर

साल दर साल (फीसदी)

16 नवंबर

सरकार ने बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा खुलासा किए जाने के एक दिन बाद एनएसओ के उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण को रद्द कर दिया। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई थी कि 2017-18 में उपभोक्ता खर्च चार दशकों में पहली बार घटा।

27 नवंबर

औद्योगिक संबंध श्रम संहिता विधेयक को संसद में पटल पर रखा गया। विधेयक में तीन कानूनों का विलय किया गया और 44 संहिताओं को मिलाकर छह संहिता बनाई गईं। इसके अलावा छंटनी के नियमों को आसान बनाया गया ताकि उद्यमों के लिए नियुक्तियां आसान बनें।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को धार देने के लिए कॉरपोरेट कर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी और नई विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया।

20 सितंबर

लक्ष्य से दूर

कुल जीएसटी संग्रह

(अप्रैल-नवंबर 201)

करोड़ रुपये में

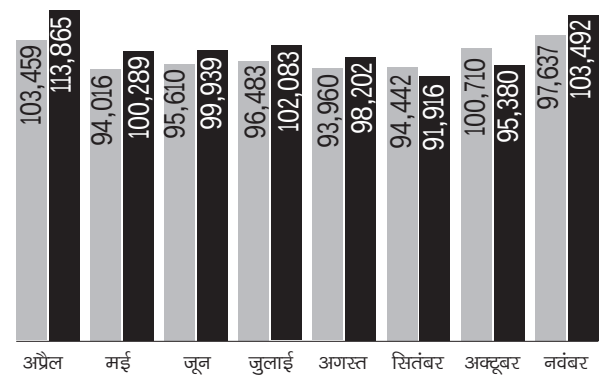

8 नवंबर

मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की सॉवरिन रेटिंग का परिदृश्य बदलकर 'स्थिर' से 'नकारात्मक' कर दिया। एजेंसी ने कहा कि आर्थिक वृद्धि के बीते वर्षों की तुलना में कमजोर पड़ने का जोखिम बढ़ा है।

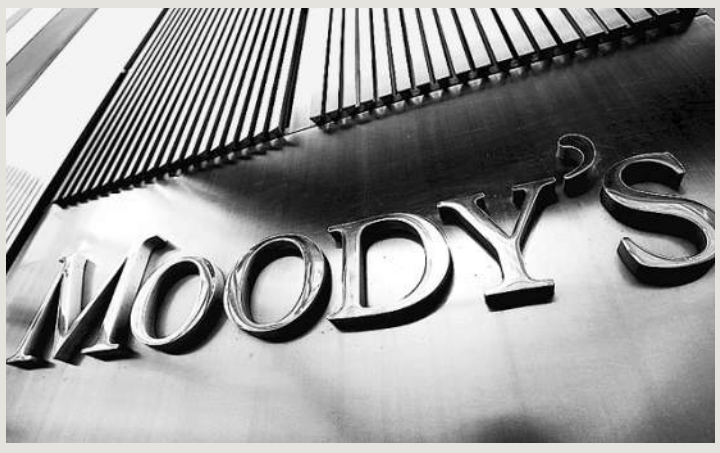

4 नवंबर

भारत ने आखिरकार क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) से बाहर रहने का फैसला किया। भारत ने कहा कि बातचीत से उसकी अहम चिंताएं दूर नहीं हुई हैं।

बढ़ती चिंता

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई साल दर साल (फीसदी)

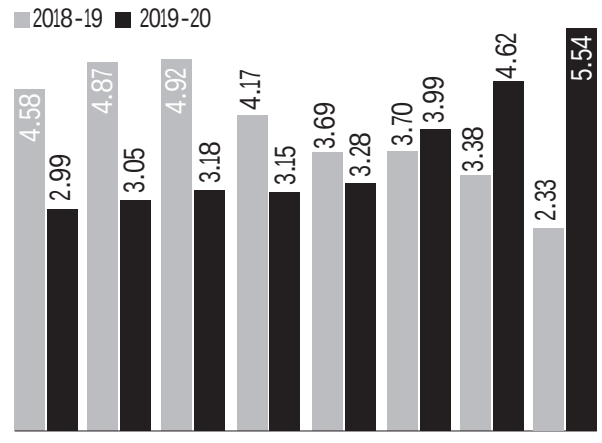

कारोबार

रफ्तार में आया ठहराव

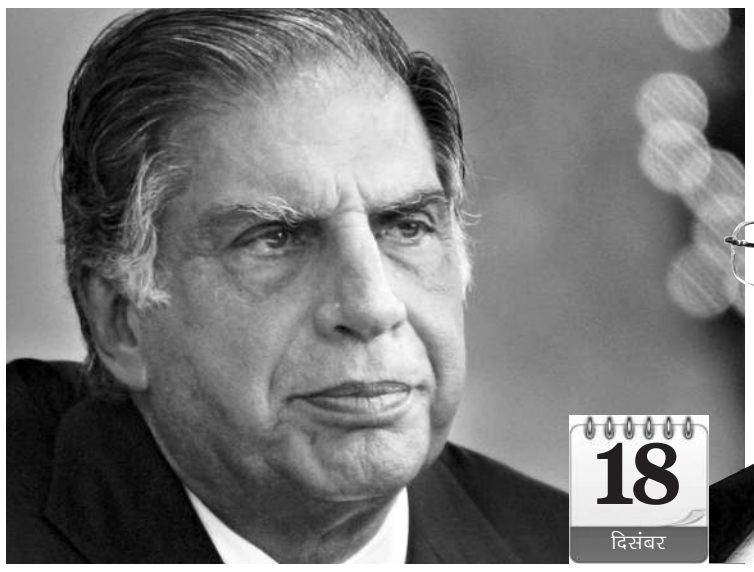

18 दिसंबर

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के चेयरमैन पद से अपदस्थ साइरस मिस्त्री को तीन साल की अदालती लड़ाई के बाद राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने इस पद पर बहाल कर दिया। न्यायाधिकरण ने कंपनी के मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की 2017 में नियुक्ति को अवैध करार दिया है। टाटा समूह को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए चार सप्ताह मिले हैं।

17 अप्रैल

देश की सबसे पुरानी विमानन कंपनी जेट एयरवेज ने 8,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में नाकाम रहने पर परिचालन रोक दिया। कंपनी ने जून में ऋण चुकाने में अक्षमता के लिए आवेदन किया है और वह अब भी खरीदार ढूंढ रही है।

30 जनवरी

कोबरापोस्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के संदिग्ध संबंधित पक्षों को ऋण देने की आरोपी होने का खुलासा किया। कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में डिफॉल्ट के बाद ऐसे ऋण 95,000 करोड़ रुपये के पाए गए। इस मामले की गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पड़ताल कर रहा है।

25 नवंबर

सुभाष चंद्रा ने ज़ी एंटरटेनमेंट में अपने परिवार की हिस्सेदारी निवेशकों को बेचने के बाद कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने यह हिस्सेदारी वे ऋण चुकाने के लिए बेची है, जो उन्होंने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दांव लगाने की खातिर लिए गए थे।

12 अगस्त

मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी तेल एवं रसायन इकाई में 20 फीसदी हिस्सेदारी सऊदी अरब की अरामको को बेचेगी। यह सौदा 75 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर होगा। कंपनी का मकसद मार्च 2021 तक खुद को कर्ज मुक्त बनाना है।

24 मई

अदाणी समूह ने विमानन क्षेत्र में उतरते हुए छह गैर-महानगर हवाई अड्डे- अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मंगलूरु और तिरुवनंतपुरम विकसित और परिचालित करने के लीज अधिकार 50 साल के लिए हासिल किए।

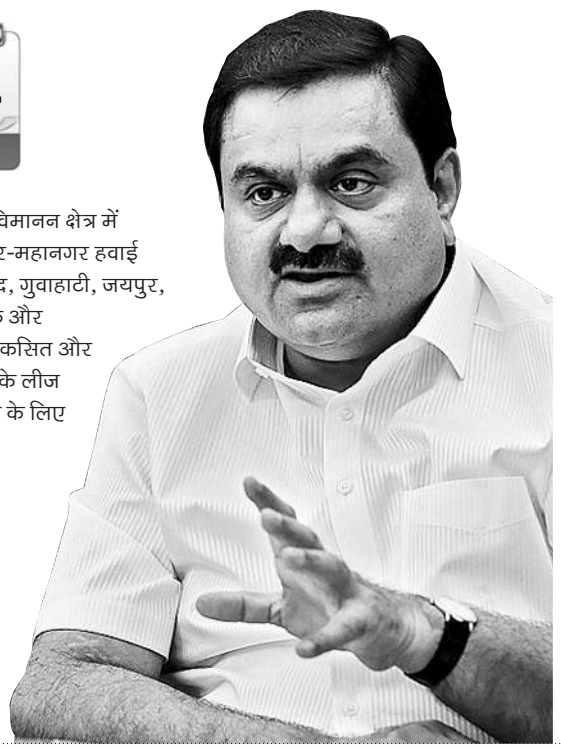

1 फरवरी

नए नियमों से फ्लिपकार्ट-वॉलमार्ट और एमेजॉन को तगड़ा झटका लगा है। इन नियमों के मुताबिक विदेशी निवेश वाले ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन कंपनियों के उत्पाद नहीं बेच सकेंगे, जिनमें उनकी हिस्सेदारी है। इसके अलावा वे उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करने के लिए विक्रेताओं के साथ विशेष विपणन समझौते भी नहीं कर सकेंगे।

10 मई

सस्ती विमानन सेवा देने वाली कंपनी इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के प्रवर्तकों के बीच दरार सामने आई। राकेश गंगवाल (दाएं) ने राहुल भाटिया पर कंपनी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और सेबी के दखल की मांग की। अब यह मामला अमेरिका और लंदन तक पहुंच गया है।

22 अक्टूबर

एक व्हिसल ब्लोअर ने इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। वह पांच साल में व्हिसल ब्लोअर के आरोपों का सामना करने वाले दूसरे सीईओ बन गए हैं। इस मामले की अभी जांच चल रही है।

10 दिसंबर

येस बैंक की धन जुटाने की योजना की कोशिशों के तहत उसे आठ निवेशक मिले हैं। इनमें तीन संस्थागत और पांच निजी कंपनियां हैं। इन निवेशकों में सबसे बड़े निवेशक कम जाने-पहचाने कनाडाई उद्यमी इरविन सिंह बराइच हैं। उनके आरबीआई के 'फिट ऐंड प्रॉपर' के मापदंड पर खरे उतरने को लेकर संदेह जताया गया है।

16 दिसंबर

एक दशक और दो प्रयासों के बाद विश्व की सबसे बड़ी इस्पात विनिर्माता आर्सेलरमित्तल को भारत में प्रवेश मिल गया। कंपनी ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया प्रक्रिया (आईबीसी) के जरिये 42,000 करोड़ रुपये में एस्सार स्टील का संयंत्र खरीदा है।

3 अक्टूबर

हाउसिंग डेवलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा धन शोधन की खातिर लिए गए ऋणों को लौटाने में डिफॉल्ट करने के बाद पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) दिवाला हो गया। पीएमसी के प्रवर्तकों राकेश और सारंग वधावन को गिरफ्तार किया गया है।

3 दिसंबर

तीन प्रमुख दूरसंचार कंपनियों- रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड ग्राहकों के लिए शुल्क 20 से 41 फीसदी बढ़ाया। यह छह वर्षों में पहली शुल्क बढ़ोतरी है।

इस क्षेत्र में अच्छी वृद्धि के बावजूद कई मौके गंवाने से मिला-जुला प्रदर्शन

बीते दशक में विमानन क्षेत्र की धीमी उड़ान

अंजलि भार्गव

एक सदी में घटनाक्रम प्रधान होते हैं। वहीं एक दशक में हस्तियों की प्रधानता होती है। ऐसा लगता है कि जॉर्ज फ्रायडमैन की यह उक्ति अन्य कहीं इतनी सटीक नहीं बैठती है, जितनी भारत के विमानन क्षेत्र में। बीते दशक में शख्सियतों का दबदबा रहा है और उनके कारनामों से ही विमानन क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आए हैं। ऐसी शख्सियतों में विजय माल्या से लेकर टोनी फर्नांडिस तक शामिल हैं।

एक दशक में बदला परिदृश्य

इन लोगों के जुनून और नियति की कहानी के अलावा इस क्षेत्र का आकार तिगुना हो गया है। इस क्षेत्र के कुल यात्रियों की संख्या 2010 में 5.2 करोड़ थी, जबकि इस साल 17 करोड़ यात्रियों के उड़ान भरने का अनुमान है। आकाश में दबदबा रखने वाले लोग भी बदल गए हैं। इस दशक की शुरुआत में हवाई यात्रा को किफायती बनाकर इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली विमानन कंपनी एयर डेक्कन (2003-2008) पहले ही इतिहास बन चुकी है और उसकी खरीदार किंगफिशर एयरलाइंस के पतन की शुरुआत पहले ही शुरू हो चुकी है।

वर्ष 2011 तक किंगफिशर का सुहाना सफर खत्म हो चुका था और वह मुश्किलों में फंस गई थी। कंपनी का परिचालन अक्टूबर 2012 में थम गया। विमानन कंपनी का लाइसेंस स्थगित कर दिया गया, सभी को कंपनी के बकाये का पता चल गया और कर्मचारी बेरोजगार हो गए। किंगफिशर के दिवालिया होने का पूरे क्षेत्र पर असर पड़ा। लीज प्रदाता और ऋणदाता भारतीय विमानन कंपनियों के साथ कारोबार करने में ज्यादा सतर्क हो गए।

हालांकि एक व्यक्ति को नुकसान से दूसरे को फायदा हुआ। किफायती विमानन कंपनी इंडिगो 2006 से अपनी मौजूदगी मजबूत कर रही थी। उसने दशक की शुरुआत में 180 ए320एस विमानों का 15 अरब डॉलर का ऑर्डर दिया। इसके पांच साल बाद कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू किया। हालांकि इसने पड़ोसी देशों तक ही उड़ानें शुरू कीं। इंडिगो से पहले शुरू होने वाली गो एयर ने जून 2011 में 72 ए320नियो विमानो का बड़ा ऑर्डर दिया। हालांकि इन वर्षों में कंपनी की प्रगति धीमी रही है। कंपनी अपने वरिष्ठ प्रबंधन को अलविदा कर रही है और इस बात का एक उदाहरण पेश कर रही है कि कैसे बहुत थोड़े शीर्ष नेतृत्व से प्रबंधन किया जा सकता है।

इसके बाद जून 2010 में इस क्षेत्र में एक नए व्यक्ति का प्रवेश हुआ। चेन्नई के कारोबारी और मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन ने स्पाइसजेट में नियंत्रण लायक हिस्सेदारी खरीदी। हालांकि मारन का विमानन क्षेत्र से प्रेम महज मोह था। उन्होंने 2015 में बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी विमानन कंपनी अजय सिंह को सौंप दी, जो पहले प्रमोद महाजन के सहयोगी थे। टोनी फर्नांडिस ने टाटा के साथ संयुक्त उद्यम में एयर एशिया इंडिया की 2014 में स्थापना की। टाटा ने उस समय कई लोगों को असमंजस में डाल दिया, जब उसने दो समानांतर उद्यमों- एयर एशिया बरहाद के साथ एयर एशिया इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ विस्तारा की स्थापना की घोषणा की। कई लोगों ने आश्चर्य जताया कि क्या यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है? उद्योग से जुड़े लोगों के लिए ऐसी बातें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन इससे मुश्किल दौर से गुजरते क्षेत्र में रोजगार बढ़े। लेकिन दोनों कंपनियों को घाटा हुआ, जो शुरुआती दिनों में लाजिमी भी है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि गुजरते समय के साथ सुधार के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं।

> जब से गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मा संभाला है, तब से एयर इंडिया की बिक्री तय मानी जा रही है। अगर शाह इसे नहीं अंजाम दे पाएं तो ऐसा और कोई नहीं कर सकता। नहीं बिकने का मतलब है कि यह विमानन कंपनी बंद होगी

इन सब घटनाक्रमों के बीच जेट एयरवेज लड़खड़ाने लगी। यह विमानन कंपनी तब से अपनी जमीन खो रही है, जब से किफायती विमानन कंपनियां इस क्षेत्र में उतरी हैं। यह खुद को पटरी पर नहीं ला सकी और पूरे दशक में बढ़ते घाटे की समस्या से जूझती रही।

कंपनी ने 2013 में एक बड़ा हिस्सा एतिहाद को बेचा और अपने परिचालन को पुनर्गठन किया, लेकिन उसकी किस्मत नहीं बदली। कंपनी के लिए अवरोध 2018 के मध्य में पैदा हुआ, लेकिन यह किसी तरह अप्रैल 2019 तक चलती रही। मगर उसके बाद इसका परिचालन बंद हो गया।

एयर इंडिया पूरे दशक के दौरान संकटग्रस्त बनी रही। यह विमानन कंपनी इस चीज की बानगी है कि कैसे कुप्रबंधन और निहित हित मिलकर इसे असफल बना रहे हैं। विमानन कंपनी में लगातार झोंका जा रहा पैसा बरबाद जा रहा है। कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है, हैंगर में खड़े विमानों की संख्या बढ़ी है और इसकी स्थिति में सुधार की संभावनाएं कमजोर बनी हुई हैं।

क्या इसका समाधान बिक्री है? जब से गृह मंत्री अमित शाह ने जिम्मा संभाला है, तब से इसे तय माना जा रहा है। अगर शाह इसे नहीं अंजाम दे सकते तो ऐसा और कोई नहीं कर सकता। नहीं बिकने का मतलब होगा कि कंपनी बंद होगी। इस विकल्प को चुनना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, जिसे लेकर पहले ही विवाद हो चुका है।

संभवतया उद्योग के लिए इस दशक में बड़ी तकलीफ की बात यह भी रही है कि नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुस्त प्रगति रही है। इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य 1997 से अब तक पूरा नहीं हुआ है। यह भी उस स्थिति में जब मुंबई शहर स्लॉट की भारी कमी से जूझ रहा है क्योंकि मौजूदा हवाई अड्डे की क्षमता पूरे उपयोग के स्तर पर पहुंच चुकी है। असल में जब से जेट के स्लॉट खाली हुए हैं, तब से अन्य विमानन कंपनियां उन्हें हासिल करने के लिए भूखे गिद्ध की तरह टूट पड़ी हैं।

वर्ष 2012 में शुरू होने वाला रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे का संकट भी हवाई अड्डा क्षेत्र के लिए नुकसानदेह रहा है। इससे हवाई अड्डा क्षेत्र की दो प्रमुख ऑपरेटरों-जीवीके और जीएमआर की बैलेंस शीट कमजोर हुई है। हालांकि दोनों कंपनियों ने कर्ज चुकाने के लिए परिसंपत्तियां बेची हैं, लेकिन भारत के अन्य हवाई अड्डों के नवीनीकरण की प्रगति थमी हुई है। यह कहना सही होगा कि पिछले एक दशक के दौरान हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे में कोई अहम सुधार नहीं हुआ है। इस बीच इस क्षेत्र में नया खिलाड़ी अदाणी समूह उतरा है, जिसने देश के छह हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और परिचालन की बोली हासिल की है।

सुरक्षा के लिहाज से देखें तो वर्ष 2010 की शुरुआत मई में एक दुर्घटना के साथ हुई। उस समय एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान मंगलूरु में क्रैश हो गई, जिसमें विमान में सवार 150 लोगों की मौत हुई। ए320 नियो में प्रैट और व्हीटनी के इंजनों में समस्या की वजह से सुरक्षा की चिंताएं बढ़ीं। हाल में ऐसी चिंताओं की वजह से ही बी737मैक्स का इस्तेमाल बंद किया गया है। हवाई यात्रा को किफायती बनाकर इसे आम आदमी की पहुंच में लाने की सरकार की योजना 'उड़ान' हकीकत में उड़ान भरने में नाकाम रही है। हालांकि यह आने वाले दशकों में भारतीय यात्रियों की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। उद्योग को उम्मीद है कि नए दशक में ईंधन की घरेलू कीमतों और हवाई बुनियादी ढांचे में सुधार के मोर्चे पर कुछ राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा लगता कि सरकार ऐसे बहुत से मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है, जो उसे न जरूरी नहीं लगते हैं। ऐसे में हर कोई यही अनुमान लगा रहा है कि क्या 2020 वर्ष 2019 की तुलना में बहुत अधिक बेहतर होगा। वर्ष 2019 को विमानन क्षेत्र के इतिहास में ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जिसमें एक दशक में पहली बार उद्योग की वृद्धि एक अंक में रही।

अटल प्रतिमा

फोटो: पीटीआई

लखनऊ में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

विरासत में मिली चुनौतियों का हल आसानी से निकला: मोदी

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश में हुए हिंसक प्रदर्शन और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि सार्वजनिक संपत्ति और सुविधाओं का लाभ पाना जनता का हक है तो उसे सुरक्षित रखना भी उसकी जिम्मेदारी है।

राजधानी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे मोदी ने कहा कि सरकारों को पांच साल का नहीं बल्कि पांच पीढ़ियों का भविष्य ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसी दिशा काम करने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने लोकभवन ऑडिटोरियम में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के बाद कहा कि उनकी सरकार को विरासत में धारा 370, राम मंदिर, बिजली, पानी, सबकों आवास, शौचालय जैसी तमाम चुनौतियां मिलीं जिनकी दिक्कतें दूर करते हुए उनका हल निकाला गया। उन्होंने नागरिकता कानून पर कहा, 'भारत विभाजन के बाद से लाखों लोग जिनमें अधिकांश दलित और पिछड़े थे, उनकी नागरिकता और सम्मान से जीने के सवाल को केंद्र सरकार ने हल किया।' *बीएस*

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2019 में छह प्रक्षेपण अभियानों और सात उपग्रह अभियानों को दिया अंजाम

इसरो ने इस साल किया कमाल

टी ई नरसिम्हन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए 2019 कामयाबी का सुनहरा साल साबित हुआ है। इस साल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने छह प्रक्षेपण यानों का अभियान सफलतापूर्वक अंजाम देने के साथ सात उपग्रह अभियानों में भी परचम लहराया। हालांकि चंद्रमा की सतह पर भारतीय यान चंद्रयान-2 को सकुशल उतारने में मिली नाकामी ने इसरो के इस स्वर्णिम सफर को थोड़ा धूमिल जरूर कर दिया।

अगर साल भर में सफल अभियानों को संख्या के हिसाब से देखें तो यह वर्ष 2018 में अंजाम दिए गए 16 अभियानों की तुलना में कम लग सकता है लेकिन इसरो ने वर्ष 2019 में कुछ बेहद अहम एवं जटिल अभियान पूरे किए हैं। चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर चंद्रयान-2 भेजने के बेहद जटिल अभियान के अलावा बेहद महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों गगनयान और आदित्य-1 की दिशा में भी वह आगे बढ़ा।

2019 साल के आईने में

गगनयान के तहत भारत अंतरिक्ष में पहली बार अंतरिक्षयात्री भेजने के मिशन पर काम कर रहा है जबकि आदित्य-1 को सूर्य की तरफ भेजा जाएगा। वर्ष 2019 की शुरुआत में इसरो ने बताया था कि इस साल उसकी 32 अभियानों को अंजाम देने की योजना है। इनमें 14 यान प्रक्षेपण, 17 उपग्रह प्रक्षेपण और एक तकनीकी प्रदर्शन अभियानों की योजना थी। इस दौरान चंद्रयान-2 के जटिल अभियान के अलावा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के विकास से जुड़े परीक्षण भी शामिल थे। एसएसएलवी को छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण यान के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

पिछले साल 16 अभियान पूरे करने वाले इसरो ने 2019 की शुरुआत किसी प्रक्षेपण से नहीं बल्कि अपने भरोसेमंद ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के उत्पादन की आउटसोर्सिंग के लिए उद्योगों के साथ सहमति ज्ञापन पर दस्तखत से किया। इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद इसरो रॉकेट तैयार करने के बजाय उपग्रहों के कामकाज पर अधिक ध्यान दे सकेगा। इसरो के चेयरमैन के शिवन का कहना है कि इससे समय एवं संसाधनों की बचत होगी।

यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत सरकार ने कई उन्नत समयबद्ध परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इनमें जीएसएलवी मैक-3 के वाणिज्यिक इस्तेमाल, अर्द्ध-क्रायोजेनिक स्तर के डिजाइन एवं विकास और मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान को मंजूरी जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। शिवन कहते हैं, 'यह साफ है कि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए इसरो के सीमित संसाधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें अनुसंधान एवं विकास के काफी काम शामिल हैं। पीएसएलवी का नियमित उत्पादन एक उद्योग कंसोर्टियम करेगा और इसरो मिशन विश्लेषण एवं योजना और नियंत्रण के कामों से जुड़ा रहेगा।'

इसरो ने एकेडेमिया के साथ अपनी भागीदारी को भी मजबूत करने की कोशिश की है। देश भर के छह अलग इलाकों में स्थित एकेडेमिया केंद्रों में इसरो अपनी छह शोध पीठ गठित करने वाला है। इन पीठों का इस्तेमाल उभरती तकनीकों के विकास की जरूरत पूरी करने और इन्क्यूबेशन सेंटर के तौर पर किया जाएगा।

प्रक्षेपण की शुरुआत 24 जनवरी को पीएसएलवी-सी44 अभियान के साथ हुई। यह पीएसएलवी के नए संस्करण पीएसएलवी-डीएल का पहला मिशन था। यह रॉकेट अपने साथ इमेजिंग उपग्रह माइक्रोसैट-आर और छात्रों द्वारा बनाया गया कलामसैट लेकर अंतरिक्ष में गया। कलामसैट को सौर समकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया।

इसके बाद इसरो ने अगले चार महीनों के दौरान तीन अभियानों को अंजाम दिया। इनमें से एक उपग्रह मई में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया। गगनयान परियोजना के लिए चालक दल के चयन और प्रशिक्षण में सहयोग के लिए इसरो ने वायु सेना के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गगनयान देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसे 2022 में प्रक्षेपित करने की योजना है।

इस बीच सरकार ने मार्च 2019 में न्यूस्पेस इंडिया के गठन की घोषणा की। इसकी कारोबारी योजना एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की तरह होगी जो इसरो की पहली व्यावसायिक कंपनी है। यह पीएसएलवी के लिए नोडल एजेंसी होगी।

जून से सितंबर तक इसरो का ज्यादा जोर चंद्रयान-2 पर रहा। इसे पहले दिन से ही कह रहा था कि यह अभियान तकनीकी रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसरो ने इसके लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की कोशिश की जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। 15 जुलाई को अंतिम क्षणों में इस अभियान को तकनीकी गड़बड़ी के कारण टाल दिया गया। इस गड़बड़ी को दूर करने के बाद चंद्रयान-2 को 22 जुलाई को 48 दिन की यात्रा पर रवाना कर दिया गया।

ऑर्बिटर को 2 जुलाई को सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया गया लेकिन विक्रम लैंडर को सुरक्षित चंद्रमा की सतह पर उतारने की इसरो की कोशिश सफल नहीं हो पाई। ऑर्बिटर को पांच साल तक सेवा में रहना था लेकिन इसमें जितना ईंधन बचा है उससे यह सात साल तक सक्रिय रह सकता है।

इस झटके के बाद इसरो ने नवंबर में फिर प्रक्षेपण की पटरी पर लौटा और उसने पीएसएलवी-सी47 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस रॉकेट ने कार्टोसैट-3 और अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का आधुनिक भू अवलोकन उपग्रह है जिसमें उच्च रिजॉल्यूशन इमेजिंग क्षमता है। यह उपग्रह पांच साल तक सेवा में रहेगा। इसका उपयोग व्यापक पैमाने पर शहरी नियोजन, तटीय भूमि के इस्तेमाल, ग्रामीण संसाधनों और बुनियादी ढांचे के विकास में किया जाएगा। साथ ही इससे सुरक्षा बलों की अंतरिक्ष से निगरानी की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। साल का समापन पीएसएलवी के 50वें मिशन के साथ हुई। पीएसएलवी-सी48 ने देश के नए जासूसी उपग्रह रिसैट-2बीआर1 और नौ अन्य विदेशी उपग्रहों को उनकी कक्षा में पहुंचाया।

शिवन ने कहा कि यह इस साल का अंतिम प्रक्षेपण होगा और इस तरह इसरो ने छह प्रक्षेपण वाहन मिशनों और सात उपग्रह मिशनों के साथ साल का समापन किया।

- **चंद्रमा के अंधेरे हिस्से पर चंद्रयान-2 भेजने के बेहद जटिल अभियान के अलावा बेहद महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमों गगनयान और आदित्य-1 की दिशा में इसरो आगे बढ़ा**
- **2019 की शुरुआत पीएसएलवी उत्पादन की आउटसोर्सिंग के लिए उद्योगों के साथ सहमति पत्र पर दस्तखत से हुई**
- **सरकार ने मार्च 2019 में न्यूस्पेस इंडिया के गठन की घोषणा की। इसकी कारोबारी योजना एंट्रिक्स कॉरपोरेशन की तरह होगी**
- **चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर सका**
- **इसरो ने एकेडेमिया के साथ भागीदारी मजबूत करने की कोशिश की है। देश भर के छह अलग इलाकों में इसरो अपने छह शोध पीठ गठित करने वाला है।**
- **इसरो अब चंद्रयान-3 की तैयारी कर रहा है जिसे नवंबर 2020 में छोड़ा जा सकता है**

आगे की राह

शिवन का कहना है कि 2020 में इसरो ने पीएसएलवी, जीएसएलवी और एसएसएलवी के साथ प्रक्षेपण की कई योजनाएं बनाई हैं। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि आने वाले साल में इसरो कितने प्रक्षेपण करेगा। उन्होंने कहा कि पीएसएलवी अंतरिक्ष में सभी स्थानों की यात्रा कर चुका है। इनमें ध्रुवीय कक्षा, भूस्थिर हस्तातंरण कक्षा, चंद्रमा और मंगल शामिल है और अब उसका अगला लक्ष्य सूर्य है। नवंबर में शिवन ने कहा था कि इसरो का व्यस्त कार्यक्रम है और मार्च 2020 तक उसके पास 13 मिशन हैं।

इसके बाद 2020 के मध्य में जीसैट-20 उपग्रह का प्रक्षेपण होना है। यह अगली पीढ़ी का पांच टन वजनी उपग्रह है जो देश की संचार क्षमताओं को बढ़ाएगा और इससे देश के ग्रामीण तथा दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसरो ने पहले कहा था कि वह एक नए रॉकेट एसएसएलवी का प्रक्षेपण करेगा जो 500 किग्रा भार ले जाने में सक्षम है। छोटे रॉकेटों के क्षेत्र में बढ़ रही वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के मद्देनजर इसका विकास किया जा रहा है। यह प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप के छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। इसरो अब चंद्रयान-3 की तैयारी कर रहा है जिसे नवंबर 2020 में छोड़ा जा सकता है और इसके जरिये एक बार फिर चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारने की कोशिश होगी।